www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित | हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 48 | गोरखपुर, 15 जून 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

एयर इंडिया दुर्घटना और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अहम बैठक शीघ्र

नई दिल्ली। अहमदाबाद से लंदन जा रहा 'बोइंग 787-8' विमान 12 जून को उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर एक मेडिकल कॉलेज परिसर में जा गिरा जिससे विमान में सवार 241 लोगों, जमीन पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और कई अन्य की मौत हो गई।

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) पहले से ही दुर्घटना की जांच कर रहा है। मंत्रालय के 13 जून के आदेश के अनुसार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता वाली इस समिति में नागर विमानन सचिव और गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सदस्य के रूप में शामिल हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू गत शनिवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान अक171 दुर्घटना की जांच और व्यापक हवाई सुरक्षा प्रोटोकॉल का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, सूत्रों ने बताया। 265 लोगों की जान लेने वाली इस दुर्घटना के बाद दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में यह पहली बैठक होगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एमओसीए के वरिष्ठ अधिकारी सुबह 10:30 बजे होने वाली बैठक में मौजूद रहेंगे।

सूत्रों के अनुसार, मंत्री विमान दुर्घटना की जांच की प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसमें अब तक बरामद किए गए साक्ष्य और जांच में अगले कदमों पर चर्चा होगी। कथित तौर पर विभिन्न विमानन और आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों से इनपुट और रिपोर्ट मांगी जाएगी।

लंदन जाने वाले बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में सवार 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से एक को छोड़कर सभी की मौत हो गई, जब विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के परिसर में एक छात्रावास की इमारत में जा घुसा। इस दुर्घटना में जमीन पर मौजूद 24 लोगों की भी जान चली गई, जिनमें पाँच मेडिकल छात्र भी शामिल थे। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने गत शुक्रवार को कहा कि डिजिटल फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स के रूप में जाना जाता है, छात्रावास की छत से बरामद किया गया है। डेटा उड़ान के अंतिम क्षणों को फिर से बनाने और त्रासदी के मूल कारण की पहचान करने में महत्वपूर्ण होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुर्घटना स्थल का दौरा किया और अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की।

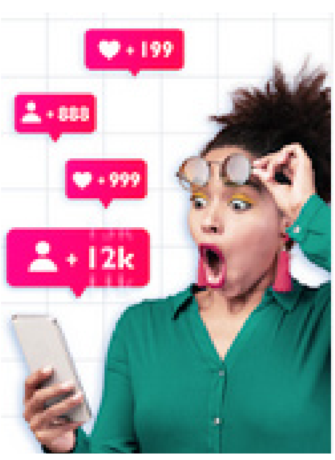
चूंकि विशेषज्ञ दुर्घटना के कारणों के बारे में अटकलें लगा रहे हैं - दोहरे इंजन की विफलता, फ्लैप की खराबी या पक्षी का टकराना - विमानन अधिकारियों ने सुरक्षा जांच बढ़ा दी है। डीजीसीए ने एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े के गहन निरीक्षण का आदेश दिया है, जिसमें जीईएनएक्स इंजन से संचालित 26 बी787-8 और सात बी787-9 विमान शामिल हैं।

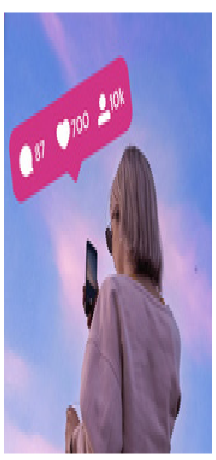
एअर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल पर एनएसजी टीम तैनात



अहमदाबाद। एअर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल पर केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) की एक टीम को तैनात किया गया है। इस विमान दुर्घटना में 265 लोगों की मौत हो गई थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एनएसजी टीम राहत कार्यों में अन्य एजेंसियों की सहायता के लिए घटनास्थल पर है और उसके पास कोई जांच करने की शक्ति नहीं है। बृहस्पतिवार को लंदन जा रहे एअर इंडिया के विमान - बोइंग 787 ड्रीमलाइनर - में 242 लोग सवार थे लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह मेघाणीनगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में करीब 265 लोगों की मौत हो गई। एनएसजी कमांडो को छात्रावास भवन में दुर्घटना स्थल पर देखा गया, जहां दुर्घटना के बाद से विमान का पिछला हिस्सा फंसा हुआ है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, डीजीसीए, अहमदाबाद अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस सहित अन्य एजेंसियां इस घटना की जांच में शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के अधिकारियों ने भी गत शुक्रवार को मेघाणीनगर में दुर्घटनास्थल का दौरा किया था।

फालोवर्स, लाइक्स और रिपोस्ट की भूख





डिजिटल युग की चकाचौंध में खोया हुआ युवा आज एक अनजानी दौड़ का हिस्सा बन चुका है। यह दौड़ न तो मैराथन है, न ही कोई रचनात्मक यात्रा । यह फॉलोअर्स, लाइक्स और रीपोस्ट्स की भूख है, जो स्क्रीन की चमक में उसे अपनी असल पहचान से दूर ले जा रही है। एक समय था जब पहचान का आधार व्यक्ति के विचार, उसकी मेहनत और उसकी नैतिकता होती थी। आज वह आधार डिजिटल आंकड़ों की रेत पर टिका है-एक ऐसी नींव जो हर नये ट्रेंड के साथ हिल जाती है। यह सिर्फ सोशल मीडिया की कहानी नहीं, बल्क एक पीढ़ी की आत्मा की खोज की कहानी है, जो अपनी सच्चाई को स्क्रॉल करने में भूल चुकी है।

सोशल मीडिया ने दुनिया को जोड़ा, लेकिन इसने व्यक्तिगत पहचान को एक बाजार में तब्दील कर दिया। इंस्टाग्राम की रील्स, टिकटॉक के वीडियो और टिवटर के 280 अक्षरों में युवा अपनी कहानी को समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कहानी उनकी नहीं, बल्कि उस छवि की होती है, जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए गढ़ी जाती है। एक 18 साल का लड़का अपनी कविता की गहराई से नहीं बल्कि अपनी प्रोफाइल की 'एस्थेटिक' से आंका जाता है। विश्वसनीय अध्ययनों, जैसे कि जर्नल ऑफ सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी (2023) में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से युवाओं में आत्म-संदेह और चिंता के मामले 30% तक बढ़े हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उस खोखलेपन की गवाही है, जो डिजिटल स्वीकार्यता की चाह में उपजता है। इस दौड़ का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह वास्तविक उपलब्धियों को हाशिए पर धकेल देता है। यह सवाल हम सबके सामने है-क्या हम उस रोशनी की तलाश में हैं, जो स्क्रीन की चमक से नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई से आती है? यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। युवा को खुद से यह पूंछना होगा कि वह कौन है-एक डिजिटल छवि, जो हर नई पोस्ट के साथ बदल जाती है, या वह आत्मा, जो अपने विचारों और कर्मों से दुनिया को बदल सकती है। जब वह इस सवाल का जवाब ढूंढ लेगा, तब उसे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।

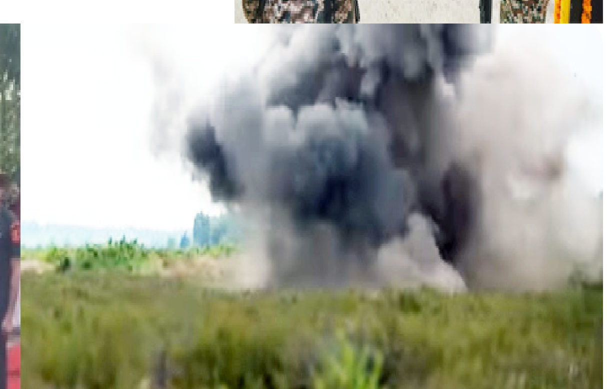
नक्सल विरोधी अभियान में सीआरपीएफ जवान शहीद

भुवनेश्वर। झारखंड सीमा के पास घने सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक आ-ईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान, सहायक उपनिरीक्षक सत्यवान कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले थे और सीआरपीएफ की 134वीं बटालियन का हिस्सा थे। वह माओवादियों द्वारा कथित रूप से लूटे गए विस्फोटकों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने के लिए ओडिशा पुलिस, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के साथ एक संयुक्त अभियान में शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान 27 मई को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक पत्थर खदान के पास माओवादियों के छापे के मद्देनजर शुरू किया गया था, जिसके दौरान कथित तौर पर माओवादियों ने विस्फोटकों का एक जखीरा जब्त किया था।

एएसआई सत्यवान कुमार सिंह की मौत हो गई। संयुक्त बल जब जंगल में तलाशी ले रहे थे, तभी एक छिपा हुआ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आ-ईईडी) विस्फोट हो गया, जिससे एएसआई सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में राउरकेला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सीआरपीएफ ने कहा कि एसएफ #सीआरपीएफ की 134 बटालियन के बहादुर सहायक उपनिरीक्षक सत्यवान कुमार सिंह ने 14 जून 2025 को राउरकेला (ओडिशा) के लंगलकाटा इलाके में चल रहे माओवादी विरोधी अभियान के दौरान एक आईईडी विस्फोट में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सीआरपीएफ हमारे बहादुर योद्धा के अदम्य साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण को सलाम करता है। हम हमेशा अपने बहादुर आदमी के परिवार के साथ खड़े हैं।







घटती गरीबी एवं बढ़ती धनाढ्यों की संख्या

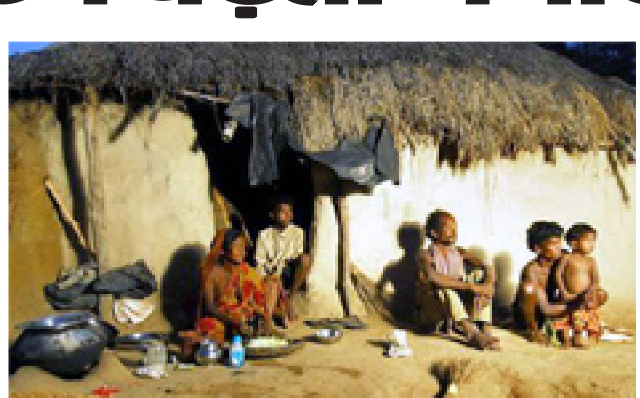
वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थान अब यह स्पष्ट रूप से मानने लगे हैं कि विश्व में भारत की आर्थिक ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में जारी किए गए एक सर्वे रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में पिछले बीते वर्ष में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या एवं उनकी संपतियों में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि विश्व के कई देशों विशेष रूप से विकसित देशों में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या एवं इनकी सम्पत्ति में वृद्धि दर लगातार नीचे गिर रही है। इसका आश्य तो अब यही लगाया जा सकता है विश्व में आर्थिक शक्ति अब पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रही है।

भारत में जिस व्यक्ति की शुद्ध सम्पत्ति 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक होती है उसे उच्च नेटवर्थ व्यक्ति (ल्ठहक) कहा जाता है। पिछले वर्ष भारत में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की औसत सम्पत्ति 8.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, जबकि विश्व में यह औसतन 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत में मिलिनेयर्स की संख्या बढ़कर 378,810 हो गई है और इनकी कुल सम्पत्ति 1.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्थात 129 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। वर्ष 2024 में भारत में 4,290 अल्ट्रा उच्च नेटवर्थ व्यक्ति निवास कर रहे थे, जिनकी कुल सम्पत्ति 53,477 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी। अल्ट्रा उच्च नेटवर्थ व्यक्ति उस नागरिक को कहते हैं जिसकी शुद्ध सम्पत्ति 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर अथवा उससे अधिक होती है।

भारत में तो उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है परंतु यूरोप में इनकी संख्या 2.1 प्रतिशत घटी है। ब्रिटेन में 14,000, फ्रांस में 21,000, जर्मनी में 41,000 उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या घटी है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या 1.7 प्रतिशत बढ़ी है तो लेटिन अमेरिका में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या 8.5 प्रतिशत घटी है। साथ ही, मध्य पूर्व में भी उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या में 2.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

क्या भारत में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की बढ़ती संख्या एवं इनकी बढ़ती सम्पत्ति से भारत में कहीं आर्थिक असमानता के गहराने का संकट तो खड़ा नहीं हो रहा है। हालांकि भारत में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की बढ़ती सम्पत्ति, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रतीक भी है। परंतु, यदि इस बढ़ी हुई सम्पत्ति का लाभ समाज के समस्त नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है तो यह सोचनीय प्रशन्न अवश्य है।

इसी संदर्भ में हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में अतुलनीय रूप से कमी दर्ज की गई है। यह भारत के लिए निश्चित ही बहुत अच्छी खबर हो सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या 34.44 करोड़ नागरिकों से घटकर 7.52 करोड़ नागरिक रह गई है। भारत में लगभग 27 करोड़ नागरिकों को अत्यधिक गरीबी से ऊपर ले आया जा सका है। विश्व बैंक की उक्त रिपोर्ट के



अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत की कुल जनसंख्या का 27.1 प्रतिशत नागरिक अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने को मजबूर था परंतु वर्ष 2022-23 आते आते यह संख्या घटकर मात्र 5.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि, इस बीच भारत की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। यह भारत में तेज गति से विकसित किए गए रोजगार के अवसरों के चलते सम्भव हो सका है। इस संदर्भ में विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं के लाभ को देश की अधिकतम जनसंख्या तक पहुंचाने के कारण भारत में बहुआयामी गरीबी को कम करने में अपार सफलता हासिल की जा सकी है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (टढक) वर्ष 2005-06 में 53.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 15.5 प्रतिशत तक नीचे आ गया है। आगे आने वर्षों में भी यदि इसी प्रकार के आर्थिक विकास दर भारत में लागू रहती है तो बहुत सम्भव है कि कुछ ही वर्षों के उपरांत संभवतः भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला एक भी नागरिक शेष नहीं रहेगा।

विश्व बैंक की उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में लगभग एक जैसी सफलता मिली है। इसी का परिणाम है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर आज 18.4 फीसदी से घटकर 2.8 प्रतिशत रह गई है। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी अत्यधिक गरीबी दर जो 10.7 फीसदी के करीब थी, वह घटकर सिर्फ 1.1 पर आ गई है। इसी तरह का एक व्यापक अंतर ग्रामीण-शहरी जीवन के आर्थिक व्यवहार में भी दूर हुआ है, यह अंतर 7.7 फीसदी से घटकर सिर्फ 1.7 प्रतिशत पर आ पहुंचा है। विशेष रूप से महिलाओं के बीच रोजगार के अवसरों में अतुलनीय वृद्धि दर हासिल की जा सकी है। ग्रामीण इलाकों में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसरों में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारी की दर 6.6 प्रतिशत तक नीचे आ गई है, जो वर्ष 2017-18 के बाद से सबसे कम है।

भारत में गरीबी दूर करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया है। इस सम्बंध में विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की गईं हैं। इन महत्वपूर्ण एवं विशेष योजनाओं में शामिल हैं - प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आयुषमान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, जैसी अनेक योजनाओं ने देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को बहुत अधिक लाभ पहुंचाया है, जिससे इन्हें गरीबी रेखा के ऊपर लाया जा सका है। इसी प्रकार, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, डिजिटल क्रांति, मेक इन इंडिया, जन औषद्धि केंद्र, विभिन्न फसल की एमएसपी पर खरीदी एवं इसके माध्यम से किसानों को आय की गारंटी देना, मखाना बोर्ड का गठन, जनजातियों का सशक्तिकरण - ग्राम समृद्धि, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन चलाना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति, किसानों को किफायती दरों पर यूरिया उपलब्ध कराना, भारत को पंख (उड़ान 2 की उड़ान और तेज हुई), विमानन के क्षेत्र में नए युग का प्रारम्भ, आदि क्षेत्रों में लागू की गई उक्त वर्णित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो अतुलनीय कार्य किए गए हैं, उससे देश में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित करने में सफलता हासिल की जा सकी है।

उक्त वर्णित विभिन्न योजनाओं को लागू करने में केंद्र सरकार ने कभी भी वित्त की कमी नहीं आने दी क्योंकि करों की वसूली में ईमानदारी एवं वित्तीय अनुशासन के चलते जीएसटी, आय कर एवं कारपोरेट करों में उच्च स्तरीय वृद्धि दर्ज हुई है। न केवल उक्त वर्णित विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्त की उपलब्धता बनी रही है बल्कि पूंजीगत खर्चों में भी अतुलनीय वृद्धि दर्ज की जा सकी है। साथ ही, बजट में वित्तीय घाटे को भी लगातार कम करने में सफलता हासिल हुई है। और तो और, केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों की कार्यप्रणाली में इस प्रकार से सुधार किया गया है कि जो उपक्रम पिछले कुछ वर्षों पूर्व तक घाटे में चल रहे थे एवं केंद्र सरकार को इन उपक्रमों को चलायमान बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी होती थी, आज ये उपक्रम केंद्र सरकार के लिए कमाऊ पूत साबित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में तो केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लाभ अर्जित किया है। इन सभी कारणों से केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आम नागरिकों के भले के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं को चालू रखने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा है एवं जिसके चलते गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे करोड़ों नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने में अपार सफलता मिली है।



राज्य में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत

शिमला । हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। शुक्रवार दोपहर को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी शिमला की बात करें तो यहां दो बजे के बाद बारिश शुरू हो गई। ऐसे में गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं, ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक बजकर तीस मिनट पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने से जहां पर प्रचंड गर्मी से राहत मिली वहीं पर इस बारिश से धुल व प्रचंड गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। अन्य क्षेत्रों में भी बादल छाए हैं। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी से राहत मिली है।

वहीं, शुक्रवार दोपहर को जिला ऊना के बड़ूही क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज तूफान के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तूफानी हवाओं के चलते बड़ूही बाजार में कई जगह पेड़ों की डालियां टूटकर सड़क पर आ गिरीं, हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने टूटी डालियों को हटाकर रास्ता साफ किया। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ती गर्मी से परेशान थे, लेकिन आज की यह बूंदाबांदी ठंडी हवा के साथ राहत लेकर आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही परिवर्तनशील मौसम की संभावना बनी हुई है।

सिरमौर जिले के नौहराधार क्षेत्र में गत दो दिनों से बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों ने जहां गर्मी से राहत की सांस ली है, वहीं किसानों और बागवानों के लिए भी यह बारिश संजीवनी साबित हो रही है। शुक्रवार को दोपहर के समय करीब आधा घंटा भारी बारिश हुई। बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि भी हुई। किसानों का कहना है कि यह बारिश टमाटर, फ्रांसबीन, शिमला मिर्च आदि के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी।

सोलन में शुक्रवार दोपहर बाद आय तेज तूफान व बारिश से नगर निगम सोलन की पार्किंग में एक विशालकाय पेड़ गिर गया। इससे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उपमहापौर मीरा आनंद ने बताया कि निगम ने संबंधित विभाग को खतरनाक अवस्था में पड़े पेड़ों को काटने के लिए प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने सरकार व प्रशासन ने आग्रह किया है कि जो कि जनहित में प्रार्थना पत्र आता है उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।

मौसम ने बदली करवट: हल्की बारिश, लोगों को मिली राहत

जैसलमेर। रेगिस्तानी जिला जैसलमेर, जो बीते कई दिनों से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चपेट में था, वहां शनिवार की सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। आमतौर पर चिलचिलाती धूप, तपती जमीन और गर्म हवाओं से जूझते लोग उस समय आश्चर्यचकित रह गए, जब सुबह आसमान में घने बादल छा गए और उसके कुछ ही क्षणों बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई। करीब 15 से 20 मिनट तक हुई इस हल्की से मध्यम बारिश ने क्षेत्र के लोगों को भीषण गर्मी से अस्थायी लेकिन बहुप्रतीक्षित राहत पहुंचाई।

पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से जिले में तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। सूरज की तीखी किरणें और दोपहर की तेज लू ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था। हालात इतने विकट हो गए थे कि न सिर्फ दिन में काम करना मुश्किल हो रहा था, बल्कि रातें भी गर्म हवाओं और उच्च तापमान के कारण बेचैनी से भर गई थीं। पंखे और कूलर भी इस भीषण गर्मी में बेअसर साबित हो रहे थे। लोगों को नींद पूरी करना तो दूर, चैन से बैठना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में शनिवार की सुबह अचानक हुई बारिश ने पूरे जिले में राहत की लहर दौड़ा दी।

सुबह उठते ही जब लोगों ने बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की बूंदों की आवाज सुनी, तो कई घरों की छतों और गलियों से बच्चे और बुजुर्ग आसमान की ओर देखने लगे। कई लोगों ने बारिश में भीगकर गर्मी से मिली इस अस्थायी राहत का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर भी जैसलमेर की बारिश के वीडियो और तस्वीरें साझा होने लगीं।

हालांकि यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। बारिश थमते ही वातावरण में उमस बढ़ गई और चिपचिपा मौसम लौट आया। लेकिन सूरज के दर्शन नहीं होने के कारण तापमान थोड़ा नियंत्रण में रहा। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों या दिनों में और बारिश हो सकती है।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, पशुपालक, निर्माण श्रमिक और दैनिक मजदूरी करने वाले वर्ग के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं रही। पिछले दिनों गर्मी की वजह से खेतों में काम करना लगभग नामुमकिन हो गया था। पशुधन के लिए चारा और पानी जुटाना मुश्किल हो रहा था। इस बदलाव से उनके जीवन में थोड़ी राहत जरूर आई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जैसलमेर जिले के लिए 15 और 16 जून को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, आंधी, गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, विशेषकर उन इलाकों में जहां निर्माण कार्य, खुले मैदान या बिजली के पोल व तार मौजूद हैं। इसके अलावा, 17 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इसका मतलब है कि जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। यह बदलाव सामान्य जनजीवन के लिए राहतदायक हो सकता है, लेकिन इसके साथ बिजली गुल होने, पेड़ गिरने या ट्रैफिक में बाधा जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं।

सभी पुराने बिजली मीटरों को प्रीपेड में किया जायेगा तब्दील

हिमाचल प्रदेश में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर, मोबाइल की तरह होंगे रिचार्ज

शिमला। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत तक सभी पुराने बिजली मीटरों को प्रीपेड में तब्दील कर दिया जाएगा। यह स्मार्ट बिजली मीटर मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज होंगे। दिसंबर 2025 तक घरों, दुकानों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बदलाव से उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के अनुसार भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। मीटर के रिचार्ज की राशि समाप्त होते ही बिजली आपूर्ति स्वतः ही बंद हो जाएगी।

प्रदेश में नए मीटरों की खरीद के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन ने टेंडर मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के निदेर्शानुसार बिजली बोर्ड ने प्रीपेड मीटर को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन ने प्री पेड मीटर लगाने की व्यवस्था के लिए कुछ माह पूर्व एक कमेटी गठित की थी। कमेटी की सिफारिशों को अब सरकार से मंजूरी मिल गई है। ऐसे में प्रबंधन ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रीपेड मीटर



लगने पर उपभोक्ता से मीटर की सिक्योरिटी राशि नहीं ली जाएगी।

प्रीपेड मीटर लगने पर प्रदेश के साढ़े 19 लाख से अधिक उपभोक्ता परिवार की जरूरत के हिसाब से मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज करवा सकेंगे। स्मार्ट मीटर में बिजली खपत और बिल की जानकारी सीधे उपभोक्ता के मोबाइल पर चली जाएगी। रिचार्ज करने के लिए बिजली बोर्ड प्रदेश के विभिन्न स्थानों में वेंडिंग मशीनें लगाएगा। रिचार्ज का पैसा खत्म होने से पहले उपभोक्ताओं को बत्ती गुल होने का एसएमएस मिलेगा। प्रीपेड मीटर कनेक्शन से बिजली चोरी पर लगाम लगेगी। केंद्र सरकार ने सभी बिजली मीटरों को प्रीपेड में बदलने की घोषणा की है। इसी कड़ी में अब हिमाचल में बिजली बोर्ड ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जरूरत के हिसाब में बिजली प्रयोग कर होगी बचत

प्रीपेड मीटर से लोग जरूरत के हिसाब से बिजली खर्च कर सकेंगे। इससे बचत ज्यादा होगी। प्रीपेड मीटर से उन परिवारों को लाभ होगा, जो एक बार में ज्यादा बिजली बिल देने की स्थिति में नहीं हैं। वे जरूरत के हिसाब से मीटर रिचार्ज कर सकेंगे। अगर कोई छुट्टियों में बाहर गया होगा तो बिजली बिल भी नहीं चुकाना पड़ेगा। अभी उपभोक्ताओं के घरों में बिजली के पोस्टपेड मीटर लगे हुए हैं। इसमें रीडिंग से ज्यादा बिजली बिल मिलने की शिकायतें आती रहती हैं। कई क्षेत्रों में दो या तीन माह का बिल एक साथ मिलता है। प्रीपेड मीटर लगने के बाद इससे निजात मिलेगी। बिजली बोर्ड की भी मैन पावर बचेगी।

सूरज और धरती की गर्मी के बीच झुलसता इंसान

गोरखपुर। आसमां से बरसती आग और धधक रही धरती पर चारो तरफ हाहाकार सी मच गयी है। शरीर को झुलसा देने वाली धूप और भीषण उमसभरी गर्मी से बिलबिला रहे लोगों को राहत पाने के लिए सारे उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। उधर बारिश को लेकर मौसम विभाग के सारे अनुमान हवा हवाई साबित होने लगे हैं। मालूम हो कि जेठ माह में शुरू हुई शरीर को झुलसा देने वाली भीषण गर्मी अषाढ़ माह में भी लोगों



सता रही है। ऐसा नहीं है कि इससे केवल मानव ही परेशान हैं, बल्कि गर्मी झेल रहे जीव जंतु, पशु पक्षियों में भी बेचैनी बढ़ गयी है। ताल, तलैया पोखरों, जलाशयों, नहरों में भी पानी का अकाल पड़ने लगा है। जिससे छुट्टा जानवरों और पक्षियों के सामने अपनी प्यास बुझाने का संकट पैदा हो गया है। हालात ऐसे बताये जा रहे हैं कि गर्मी से बेहाल पक्षी अपने घोंसलों में ही दुबके पड़े रहना मुनासिब समझ रहे हैं। एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में बिजली की आंखमिचौली भी सिरदर्द बन गया है। स्थिति ऐसी बतायी जा रही है कि बिजली की अनगिनत बार की आवाजाही ने नाको दम कर दिया है। हवा के झोकों और हल्की बारिश में बिजली की आपूर्ति चल पाना नामुमकिन सा हो गया। अलावां इसके लाइन में बार बार आने वाले फाल्ट तथा पर्सनल कम्पलेंट को अटेंड करने के लिए दर्जनों बार होने वाले शट-डाउन से भी आपूर्ति के बाधित होते रहने का संकट झेलते रहना उपभोक्ताओं की नियति बन चुकी है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली सरकारी तथा गैरसरकारी एजेंसियों का मानसून के पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने का पुवार्नुमान बार बार हवा हवाई साबित हो रहा है। बताते चलें कि इस वर्ष देश में केरला तट पर मानसून 8 दिन पूर्व ही पहुंच गया। इसके आधार मौसम विज्ञानी दावा करने लगे कि मानसून का आगमन पहले हो जाने से बर्षा सामान्य से अधिक होने के साथ ही देश के सभी हिस्से में भी मानसून गत वर्ष की अपेक्षा समय से पूर्व पहुंच जायेगा। लेकिन पूर्वी यूपी में मानसून के 15 जून तक पहुंचने के तय समय के आने में महज दो दिन शेष रह जाने के बाद भी मानसून के आने का आसार नजर नहीं आना मौसम विभाग का अनुमान हवा हवाई प्रतीत हो रहा है।

एनक्वास सर्टिफिकेट धारक वाराणसी देश का पहला जिला बना

वाराणसी। मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा समेत 92 उपकेंद्र, 11 स्वास्थ्य केंद्र (एक सीएचसी और दस पीएचसी) को एनक्वास सर्टिफिकेट मिला है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला वाराणसी देश का पहला जिला बन गया है।

अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके आधार पर ही नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टेंडर्ड (एनक्वास) सर्टिफाइड किया जाता है। सीएमओ डॉ. संदीप चौधरी ने बताया कि जिले की कुल 104 चिकित्सा इकाइयों में शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर, 10 शहरी व ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 92 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (स्वास्थ्य उपकेंद्र) को अब तक एनक्वास से प्रमाणित किया गया है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के अन्य सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने एनक्वास के लिए नामांकन किया है। इसके साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के समस्त सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी कायाकल्प और एनक्वास के तहत मूल्यांकन प्रक्रिया की जा रही है।

अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, अगली सुनवाई 21 को

प्रयागराज। विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के आदेश को चुनौती देने वाली अब्बास अंसारी की अर्जी पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। सरकारी वकील की आपत्ति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 21 जून को निर्धारित की है। सरकारी वकील ने लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सूच्य है कि 31 मई 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने अब्बास अंसारी को विवादित हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. साथ ही 11,000 रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया था।यह मामला मऊ शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान तीन मार्च को पहाड़पुरा मैदान में आयोजित एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने प्रशासन के खिलाफ उकसाने वाले बयान दिए थे। जनसभा में उन्होंने कथित रूप से कहा था कि चुनाव जीतने के बाद प्रशासन से हिसाब-किताब किया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा। इस भाषण के बाद तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी (गाजीपुर निवासी) के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 171-एफ, 186, 189, 153-ए, 120-बी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी।

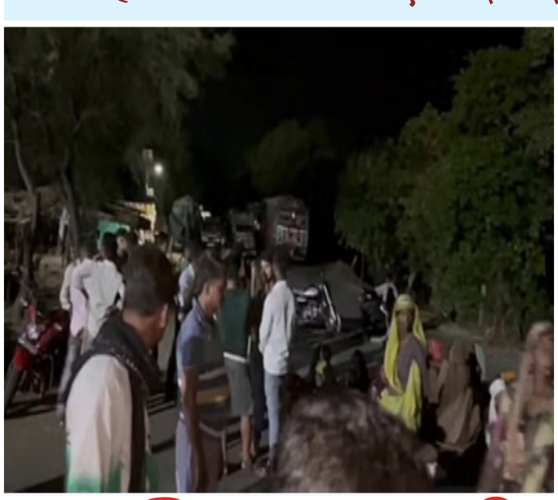
भारत की दशा व दिशा बदलने वाले हैं मोदी सरकार के 11 वर्ष

मेरठ। प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री व सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के 11 वर्ष भारत की दशा और दिशा बदलने वाले रहे हैं। ये कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में डॉ. दिनेश शर्मा ने मोदी सरकार की नीतियों को गिनवाया। सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकारों में गरीब कल्याण का भाव छिपा हुआ है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट की ताकत बना है। 11 वर्ष में कार्य संस्कृति में बदलाव, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति, महंगाई पर नियंत्रण, आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर रहा है। प्रेसवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष शिवकुमार राणा, पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी, मनिंदरपाल सिंह आदि मौजूद रहे।

डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं के सम्मान का कवच है। बुजुर्गों का स्वाभिमान है। युवाओं का गौरव है और भारत की रक्षा का संकल्प है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। पहले लोग आतंकवादियों से डरकर भागते थे, अब भारतीय सेना से डरकर आतंकवादी छिप रहा है।

कार्यकर्ताओं की अनदेखी के प्रश्न पर सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि दूसरी पार्टी के कार्यकताओं से भाजपा कार्यकताओं की तुलना ना कीजिए। भाजपा के कार्यकताओं का लक्ष्य पद प्राप्त करने से कहीं अधिक राष्ट्रवाद की स्थापना में रहता है। उचित समय पर उचित सम्मान कार्यकताओं को दिया जाता है। हर कार्यकर्ता का सम्मान पार्टी के साथ जुड़ा है।

▶ नन्हीं बच्ची के साथ ऐसी दरिन्दगी... इंसानियत भी हुई शर्मसार



बुधवार को कानपुर के हैलट अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई है। कानपुर प्रशासन से बात कर तीन डॉक्टरों के पैनल से मासूम के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बच्ची के परिजन कानपुर में ही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इस मामले की चार्जशीट वह जल्द से जल्द कोर्ट में दाखिल कराएंगे। आरोपी फिलहाल जेल में है।

पलाश बंसल,
पुलिस अधीक्षक, बांदा





आठ दिन तक बच्ची जूझने के बाद जिंदगी की जंग हार गई

बांदा । मासूम तो बस टॉफी लेने गई थी, किसी को क्या पता था कि लौटकर कभी मां की गोद में मुस्कराएगी भी नहीं। तीन साल की नन्हीं बच्ची को दरिंदे ने मासूमियत के नाम पर ऐसी सजा दी कि इंसानियत भी शर्म से झुक गई। फिर भी बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी...और पूरे आठ दिन तक कानपुर के हैलट अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ती रही।

आखिरकार...माता-पिता और इलाज कर रहे डॉक्टर से मासूम कुछ कह भी नहीं पाई और आंखों में दर्द समेटकर दुनिया को आठवें दिन बुधवार को अलविदा कह गई। चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते मंगलवार (तीन जून) को तीन साल की मासूम के साथ एक शादीशुदा युवक सुनील निषाद ने टॉफी और पान मसाला लाने का झांसा देकर उसे अपने घर बुलाया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब वह बेहोश हो गई, तो आरोपी ने उसे मछली रखने वाले थमाकोल के बॉक्स में भरकर साइकिल पर रख लिया और गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर जंगल में मरा समझकर फेंक आया। दुष्कर्म की शिकार तीन साल की बच्ची बुधवार सुबह हमेशा के लिए सो गई। वह जब भर्ती हुई तो कोमा में रही है। इसके बाद डीप कोमा में चली गई। पांच विभागों के विशेषज्ञों की टीम खूब जूझी और फिर हार गई। बच्ची को कार्डियक अरेस्ट हुआ। सांसें थमने के बाद डॉक्टरों से लेकर पैरा मेडिकल स्टॉफ के आंखों में आंसू रहे। बोले कि यह दुनिया किस हैवानियत की तरफ जा रही है? बच्ची को जब पीडियाट्रिक आईसीयू में भर्ती किया गया, तो उस वक्त उसके मस्तिष्क में सूजन थी।

डॉक्टरों का कहना है कि गला दबाने की वजह से उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई। वह कोमा की स्थिति में पहुंच गई। इसके साथ ही मासूम के जननांगों पर गहरी चोट रही। पाखाना और पेशाब का रास्ता क्षतिग्रस्त होकर एक हो गया। इससे बहुत अधिक खून शरीर से बह गया था।

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला के अनुसार, वह तकरीबन ब्रेन डेड की स्थिति में भर्ती हुई थी। पाखाने का अलग रास्ता बनाने के लिए ऑपरेशन करने के लिए बच्ची के पिता ने अनुमति नहीं दी थी। परिजनों ने बच्ची की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। जब शाम होते-होते बच्ची का पता न चला, तो परिजनों ने चिल्ला पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रात करीब दो बजे जंगल से मासूम को बेहोशी की हालत में बरामद किया। शरीर पर चोटों के निशान थे, और आंखों में डर समाया हुआ था। उसे तुरंत जिला अस्पताल, फिर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, और वहां से कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया। आठ दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद बुधवार को मासूम ने दम तोड़ दिया।

कानपुर प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन डॉक्टरों का विशेष पैनल गठित कर बच्ची का पोस्टमार्टम कराया। परिजन इस समय कानपुर में ही हैं। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि परिजन अंतिम संस्कार कानपुर में करें या बांदा लाएं, यह उनका निर्णय होगा। चिल्ला थाना क्षेत्र के गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

तीन जून मंगलवार को चिल्ला के एक गांव में बच्ची के साथ हुई हैवानियत के आरोपी को पकड़ने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा था। रात में ही उन्होंने बांदा-कानपुर हाईवे पर जाम लगाया था। पुलिस ने बुधवार तड़के आरोपी सुनील निषाद को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी थी। इलाज के बाद बुधवार को जेल भेज दिया था। आरोपी सुनील निषाद के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो, अपहरण, जानलेवा हमला समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसकी विवेचना चिल्ला थाना एसएसआई रामदिनेश तिवारी कर रहे हैं।

तीन वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता मासूम के मामले में सियासी आरोप-प्रत्यारोप भी लगने शुरू हुए थे। सपा के पूर्व सांसद विशंभर प्रसाद निषाद के मोबाइल फोन में सुबह करीब 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज वायरल हुआ था। मैसेज में साफ लिखा था कि दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई है। बच्ची से हैवानियत करने वाला राज्यमंत्री का करीबी है। इस मैसेज का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मीडिया सेल में बयान जारी कर इसे अफवाह और बच्ची का इलाज जारी होने की बात कही थी। हालांकि, बाद में पूर्व सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने बयान में कहा था कि उन्होंने इसे डिलीट कर दिया है। उधर, भाजपा जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मंत्री और सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास बताया था।

लंबी दूरी और कम वेतन में काम करना युवाओं को मंजूर नहीं

लखनऊ। रोजगार की तलाश तो है, लेकिन 1300 किलोमीटर दूर जाकर कम वेतन में काम करना युवाओं को मंजूर नहीं। अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में बुधवार को एमआरएफ कंपनी की ओर से आयोजित रोजगार मेले में युवाओं ने इसी सोच के चलते रुचि नहीं दिखाई।



गुजरात और हैदराबाद प्लांट के लिए मैकेनिक्स के 200 पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया रखी गई थी, लेकिन केवल 22 अभ्यर्थी ही इंटरव्यू देने पहुंचे। इनमें से 12 का चयन हुआ। मोहनलालगंज निवासी रवि कुमार ने बताया कि उन्होंने 2024 में आईटीआई पास किया था। उन्हें जब यह पता चला कि पोस्टिंग 1300 किमी दूर होगी और वेतन सिर्फ 18 हजार रुपये, तो उन्होंने नौकरी स्वीकारने से इनकार कर दिया। वहीं, मलिहाबाद के संतोष कुमार ने बताया कि उनके एक मित्र ने पहले अहमदाबाद की निजी कंपनी में नौकरी की थी लेकिन महंगाई और खर्च के चलते वह कुछ ही महीनों में लौट आया।

आईटीआई के प्लेसमेंट अधिकारी एमए खान ने बताया कि एमआरएफ कंपनी मैकेनिक्स के 200 पदों पर भर्ती कर रही है। काम में अनुभव बढ़ने पर वेतन में इजाफा भी किया जाएगा। उन्होंने कम उपस्थिति का कारण प्लांट की दूर लोकेशन को बताया। हालांकि, चयनित युवाओं के प्रति कंपनी ने आभार जताया है।

काउंसलर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रतिष्ठित कंपनी में पहली नौकरी करना कॅरिअर की पहली सीढ़ी है और यही अनुभव आप की सफलता में मददगार साबित होता है। इसलिए दूरी की वजह से पहली नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। एक-एक कदम पर संघर्ष आप के भविष्य में मार्गदर्शक बनकर साथ रहती है।

शहर हो या प्रदेश बेहतर अवसर मिलने पर जरूर जाएं।

अलीगंज स्थित राजकीय आईटीआई परिसर में गत बृहस्पतिवार को सैमसंग कंपनी की ओर से रोजगार मेला लगाया जाएगा। कंपनी, नोएडा प्लांट के लिए अप्रेंटिसशिप के 70 पदों पर भर्ती करेगी। प्लेसमेंट अधिकारी एमए खान ने बताया कि आईटीआई पास विद्यार्थी रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं।

चयन की प्रक्रिया साक्षात्कार के आधार पर होगी। चयनित होने पर कंपनी की ओर से 16 हजार रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आ-ईटीआई परिसर में सुबह 10 बजे से अपने दस्तावेज के साथ रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं।

धूप की चपेट में आने से एक की मौत



वाराणसी । चौबेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उमरहां निवासी बीरबल राजभर (45) की चिलचिलाती धूप की चपेट में आने से गत शुक्रवार को दोपहर में मौत हो गई। ग्राम प्रधान ऊदल पटेल ने बताया कि दोपहर में वह उमरहां बाजार जाने की बात कह कर घर से निकला था। बताया जाता है कि लगभग तीन बजे कुछ लोगों ने उमरहां बाजार में वाराणसी-गाजीपुर राजमार्ग पर स्थित आंख के नीजी अस्पताल के सामने सड़क पर गिरा देखा। लोगों ने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में चौकी प्रभारी रोहित सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए परिजनों को सूचित किया। इसके बाद बीरबल को पीएचसी चिरईगांव लेकर पहुंची, यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चौबेपुर प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश तिवारी ने बताया कि शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शिवपुर भेज दिया।

भूमि संरक्षण विभाग ने तैयार की असि नदी के जीर्णोद्धार की सर्वे रिपोर्ट

वाराणसी। भूमि संरक्षण विभाग ने असि नदी के जीर्णोद्धार की सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है। डीएम को भेजी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना अतिक्रमण हटाए नदी का जीर्णोद्धार संभव नहीं है। चितईपुर बाहरी में नदी के क्षेत्र में निर्माण कार्य कर घर और औद्योगिक क्षेत्र बना लिया गया है। वहां नदी की चौड़ाई कुछ जगहों पर 2.5 से तीन मीटर ही बची हैं। नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया गया है।

इसी तरह करौंदी, करमजीतपुर, नेवादा, सरायनंदन, सुंदरपुर, नरिया, साकेत नगर और नगवां में न केवल नदी के अंदर निर्माण कार्य हुआ है बल्कि पास के घरों का कूड़ा भी नदी में फेंका जा रहा है। इससे नदी का क्षेत्र सिकुड़ कर और कम हो गया है। बदबू से किनारे खड़ा होना भी मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक असि नदी के उद्गम स्थल कंदवा झील से लेकर अस्सी घाट तक नदी के कुल आठ किमी के मार्ग का सर्वेक्षण किया गया। सर्वे के दौरान पाया गया कि उद्गम स्थल पर सिल्ट और गाद जमा हो जाने की वजह से अपवाह क्षेत्र का जल संग्रहण करने की क्षमता समाप्त होने को है। उद्गम स्थल पर नदी अवशिष्ट दशा में आ गई है। आगे चलने पर नदी में घरों एवं रिहायशी क्षेत्र का अवशिष्ट व प्रदूषित जल मिलना शुरू हो गया है। उद्गम से एक किमी आगे तक दो तालाब प्राचीन समय के बने हुए हैं। उनमें गंदा प्रदूषित जल पाया गया। जो अब जलमग्न भूमि के रूप में बचा है। इससे नदी का क्षेत्र सिकुड़ कर कम हो गया है और बदबू से किनारे खड़ा होना भी मुश्किल है। क्षेत्र के निवासी इस नदी को अब नाला के नाम से संबोधित करते हैं। विभाग ने सुझाव देते हुए कहा है कि सबसे पहले उद्गम स्थल के जीर्णोद्धार की जरूरत है। अतिक्रमण किए गए निर्माण को हटाने की आवश्यकता है। पूरा नदी का क्षेत्र वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिना अतिक्रमण हटाए वर्तमान स्थिति में नदी का जीर्णोद्धार कार्य करना संभव नहीं है। बता दें कि पिछले महीने डीएम ने एक बैठक में विभाग से असि नदी के जीर्णोद्धार करने के लिहाज से भूमि संरक्षण अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। पिछले साल जुलाई से पहले असि नदी को मुक्त कराने की योजना के तहत कंदवा से कंचनपुर तालाब तक अधिकारियों ने मुआयना किया था और अतिक्रमण हटाने का खाका भी तैयार किया था। बाढ़ के पहले ही अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन अगस्त से लेकर नवंबर के बीच धार्मिक आयोजन और त्योहारों के चलते इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कंदवा से अस्सी घाट तक असि नदी अब पूरी तरह नाले में तब्दील हो चुकी है।





शाहजहांपुर। 21 मई से दस जून तक चलने वाले वाले ग्रीष्मकालीन समर कैंप का मंगलवार को समापन हो गया। अंतिम दिन छात्र-छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर धूम मचाई।

समर कैंप: छात्रों ने सीखा गुलदस्ता बनाना

कलवारी, बस्ती। आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय में चल रहे समर कैंप में बीते सोमवार को छात्राओं ने गुलदस्ता बनाना सीखा। समर कैंप में कुल 10 बच्चे आए थे। अनुदेशक रत्नेश सिंह ने बच्चों से कहा कि घर में बेकार पड़ी चीजों को मिलाकर गुलदस्ता बनाया जा सकता है। जो देखने में आकर्षण होता है, इसको कहीं भी सजा सकते हैं। शिक्षामित्र सुनील कुमार चौधरी ने बच्चों को नृत्य तथा गायन सिखाया।

समर कैंप का समापन छात्राओं ने सुनाया अनुभव

देवरिया। पीएमश्री कस्तूरबा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवरिया में समर कैंप सत्र 2025- 26 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरूआत सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना से हुआ। समर कैंप की नोडल प्रभारी कामिनी पांडेय ने इसके आयोजन के उद्देश्य पर चर्चा की। कैंप में प्रतिभाग किए छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किए। इसे लेकर उनमें जबरदस्त उत्साह रहा। इस अवसर पर छात्राओं ने स-ांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

क्या हो गया है इन औरतों को?

अब ये आईना क्यों नहीं झुकातीं?
क्यों चलती हैं तेज हवा सी,
क्यों बातों में धार रखती हैं?
कल तक जो आंचल से डर को ढँकती थीं,
अब क्यों प्रश्नों की मशालें थामे हैं?
क्या हो गया है इन औरतों को –
जो रोटी से इंकलाब तक पहुंच गईं?
कोमल थीं, हाँ, थीं नर्म हथेलियाँ,
अब उनमें तलवार क्यों उग आई?
क्या प्रेम मर गया है इनकी धमनियों में,
या समाज की मार ने उसे लहूलुहान किया?
कर्नाटक की उस स्त्री को देखो –
जिसे अब हर चैनल पर नंगा किया गया,
अपराध की खबर कम थी,
उसके चेहरे की लिपस्टिक ज्यादा दिखी।
कहां चूक हुई परवरिश में?
ये सवाल अक्सर औरतों के लिए होता है,
मगर जब बेटे खंजर बन जाते हैं,
तो माँ की ममता ही ढाल बना दी जाती है।
क्या स्त्री सिर्फ.सहने को बनी है?
या वो भी ज़िन्दा प्राणी है –
जिसे मोह भी होता है,
और मोहभंग भी।
कोई नहीं पूछता कि क्यों टूटी वो?
किसने उसके सपनों को कुचला था?
क्यों उसका अंत अपराध में हुआ,
शायद वह भी कभी एक गीत थी...
इन औरतों को कुछ नहीं हुआ है,
ये बस अब मौन नहीं रहीं,
अब वे दोषी भी हैं, न्याय की भूखी भी,
अब वे देवी नहीं – मनुष्य बन रही हैं।
क्या हो गया है इन औरतों को?
कुछ नहीं...
बस उन्होंने 'होना' शुरू किया है।

-प्रियंका सौरभ

राज्य में भीषण गर्मी का दौर, जनजीवन अस्त व्यस्त रातें सामान्य से भी अधिक गर्म

लखनऊ। नौतपा के बाद पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मई के उलट जून की गर्मी लोगों को परेशान करने वाली रही। खास बात यह रही कि लू के साथ कई जगह पर उमस का भी सामना करना पड़ा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी और लू चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तपिश के साथ पूर्वा हवाओं के असर से हो रही उमस से लोग बेहाल हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिम में दो-तीन दिन लू की परिस्थितियां जारी हैं।

गुरुवार को कुछ समय के लिए आसमान पर बादल भी देखे गये लेकिन इसके थोड़ी देर बार फिर धूप जस की तस होती गई। मौसम विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, झांसी में लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा,



प्रदेश के सबसे गर्म जिले- आगरा- 45.4, उरई- 45.2, बांदा- 44.8, झांसी- 44.7, प्रयागराज 43.8, सुल्तानपुर- 43.5, कानपुर 43.4, वाराणसी- 43.3, इटावा- 43.2, हमीरपुर- 43.2 बताये गए।

औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर में लू के लिए येलो अलर्ट है। पश्चिमी-तराई के नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर जैसे कुछ जिलों में दिन में लू चलने के साथ उष्ण रात्रि की संभावना है। यानी यहां रात सामान्य से ज्यादा गर्म रहेगी।

गत बुधवार को बुंदेलखंड, आगरा मंडल और दिल्ली एनसीआर के जिले प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। झांसी और आगरा में तापमान 45 डिग्री के आसपास रहा। वहीं प्रयागराज, उरई, वाराणसी, सुल्तानपुर में भी तपिश और गर्म हवा के थपेड़ों से लोग बेहाल रहे। बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर में लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इस विषय में अतुल कुमार सिंह, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, पश्चिमी-तराई के नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर जैसे कुछ जिलों में दिन में लू चलने के साथ रातें उमस भरी रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में दो से तीन दिन लू की परिस्थितियां जारी रहेंगी। वहीं बृहस्पतिवार को पूर्वांचल व अन्य हिस्सों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के संकेत हैं।

जिंदगी

डरी -डरी सी दहशत से भरी जिंदगी
पग -पग पर भय से भरी जिंदगी
मुड -मुड सी पलट से भरी जिंदगी
सूनी राहों पर दबोची जा रही जिंदगी।
हैवानियत से सनी जा रही जिंदगी
हर चौराहों पर अब चीख रही जिंदगी
चीखों को रोकों जरा हैरान है जिंदगी
दुष्कर्मियों पर कसों फंदा रो रही जिंदगी।
बलात पीड़ित की सिसकती रही जिंदगी
सुरक्षा की सबसे मदद मांग रही जिंदगी
कलयुग भी हैरान देख ये दुःख भरी जिंदगी
गुहार किससे करें ढूंढ़ रही आंसू भरी जिंदगी।
स्तब्ध है सारी दुनिया देख लाचार भरी जिंदगी
बेटियों की ये दशा कहा गई सुरक्षा भरी जिंदगी
कड़ी सजा कब मिले ये इंतजार कर रही जिंदगी
बिना भय के रह सके ये प्रार्थना कर रही जिंदगी।

संजय वर्मा दृष्टि
मनावर जिला धार मप्र

पार्किंग व्यवस्था के अभाव में आवागमन दुश्वार

देवरिया। जिले में रोजाना दो और चार पहिया वाहनों की संख्या बढ़ रही है। शहर में पार्किंग का इंतजाम नहीं होने से जिला मुख्यालय वालों को मजबूरी में अपने वाहन को सड़क के किनारे खड़ा करना पड़ता है। इससे राहगीरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में मिनटों की दूरी घंटों में तब्दील हो जाती है।

समस्या पैदा न हो और बेरोक टोक वाहनों की आवाजाही के लिए जिम्मेदारों की ओर से ठोस पहल नहीं की जा रही है। शहर के सिविल लाइंस, मालवीय रोड, गोरखपुर रोड, कोतवाली रोड, कोऑपरेटिव चौराहा से लेकर हनुमान मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग पर दिनभर जाम की स्थित बनी रहती है। शहर में रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही बनी रहती है। अधिकतर दो और चार पहिया वाहनों से आते हैं। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण यातायात नियमों का उल्लंघन कर वह अपने वाहन मालवीय रोड पर बने डिवाइडर के दोनों तरफ खड़ा करकाम निपटाने चले जाते हैं।

सिविल लाइंस रोड मुख्य मार्ग होने के कारण दिनभर बडे वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। इसी मार्ग पर कई सरकारी विभाग होने के कारण लोगों का आना- जाना लगा रहता है। विभागों में जरूरी कार्य से आए लोग अपने वाहन को सड़क की पटरी तक खड़ा करते देते है। इसके चलते सिविल लाइंस रोड पर भी दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। गोरखपुर रोड पर कई बैंक शाखाएं और बड़े प्रतिष्ठान हैं। सोमवार को इनके सामने दो पहिया वाहनों की कतार लगी दिखी। दोपहर एक बजे सिविल लाइंस रोड पर कचहरी चौराहा स्थित शिव मंदिर के पास दुकान के बाहर आधी सड़क तक बाइकें कतार से खड़ी दिखीं। दोपहर 1:20 बजे सुभाष चौक से मालवीय रोड की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक बैंक के सामने आधी सड़क तक बाइक खड़ी मिलीं।

डीएम आवास से कोतवाली की तरफ जाने वाले मार्ग पर दोपहर 1:40 बजे एक अस्पताल और बैंक के सामने वाहनों के खड़ा होने से राहगीरों को जाम से जूझना पड़ा। यहां करीब आधे घंटे तक तेज धूप में जाम में लोग फंसे रहे। सिविल लाइंस रोड पर नाला सफाई के दौरान निकाला गया सिल्ट सड़क के किनारे लगा देने से इस मार्ग पर जाम की स्थिति बन रही है। दोपहर दो बजे न्यू कॉलोनी मोहल्ले में कई निजी अस्पतालों के पास पार्किंग सुविधा नहीं होने के कारण लोग अपने वाहन को सड़क पर खड़ा कर रखा था।

'बेवफाई की हनीमून डायरी'



मैंने देखा था एक जोड़ा
हाथों में हाथ, आँखों में स्वप्न लिए
वो कहते थे -'हमसफर'
पर शायद किसी एक के लिए
ये सफर सिर्फ अंत था।
मेघालय की वादियों में
जहाँ झीलें चुपचाप सब सुनती हैं,
वहीं गूंजा था एक मौन चीत्कार
एक प्रेमी पति,
जो पत्नी के हृदय में नहीं,
उसके षड्यंत्र में जी रहा था।
राजा
जिसे लगा था कि वह 'राजकुमारी' ले आया है
असल में एक
बेवफाई की तलवार को गले लगाया था।
प्रीति अब सौदा बन चुकी है,
शादी अब स्क्रिप्ट है,
जहाँ प्रेमी मंच के पीछे
और पति, दर्शक दीर्घा में बैठा अंतिम दृश्य देखता है –
अपनी ही हत्या का।
सोनम!
तेरी मुस्कान में क्या सच में कोई मोती था?
या वह जहर था
जो तूने राजा के सपनों में घोल दिया?
तेरे 'आई लव यू' में
वो आई कितना भारी था
कि यू को मारना पड़ा?
ये कैसा युग है?
जहाँ हनीमून प्लानिंग नहीं,
हत्या की प्लॉटिंग होती है
जहाँ पत्नी, प्रेमी को गाइड करती है -
ह्लअब गिरा दो उसे घाटी से, कैमरा ऑफ है।
नॉर्थ ईस्ट के बादलों ने
शायद पहली बार
किसी की चीख को नहीं बरसाया
बल्कि उसे निगल लिया –
जैसे समाज निगलता है सवालों को।
ये हत्या नहीं सिर्फ एक व्यक्ति की
बल्कि हर उस भरोसे की है
जो विवाह के सात फेरों में
सात जन्मों तक चलने का वादा करता है।
अब प्रेम,
लॉक स्क्रीन की डीपी तक सीमित है
और वफादारी,
एप इंस्टॉल करने जितनी अस्थायी।
कितना बदला है युग
जहाँ पहले
पत्नी पति के पीछे सती हो जाती थी
अब पति को स्वाहा करके
बॉयफ्रेंड के साथ बुलेट पर घूमती है।
कहते हैं –
रिश्ते भगवान बनाता है
लेकिन आजकल ह्लरिपोर्टरह्व बनाता है
जो शव की तस्वीर खींच
'ब्रेकिन्ग न्यूज' लिखता है।
राजा तो चला गया
लेकिन सोनम के कारण
मेघालय बदनाम हुआ
पर्यटन पर ग्रहण लगा
और समाज ने फिर से
एक अपराध को 'इवेंट' बना दिया।
ये कविता कोई अंत नहीं
ये शुरूआत है
हर उस चेतावनी की
जो हमें सिखाए –
कि शादी कार्ड से नहीं,
चरित्र से तय होनी चाहिए
और हनीमून पर जाने से पहले
दिल की जांच होनी चाहिए।



-प्रियंका सौरभ

विद्यालय के बगल में गंदगी, दुर्गंध, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव का खतरा

नगर बाजार (बस्ती)। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के पास गंदगी और इससे उठ रही दुर्गंध से छात्राएं परेशान हैं। बरसात के मौसम में उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा है। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय के बगल गंदगी से बहुत परेशानी हो रही है। गंदा पानी व कीचड़ भरा होने से यहां मच्छरों की भरमार है। ऐसे में बीमारी फैलने का खतरा है। जबकि इसी विद्यालय से सटे बीआरसी भी है। वार्डेन नीलम पांडेय ने बताया कि विद्यालय के बगल बड़ा गड्ढा है। उसमें हमेशा बदबूदार व कीचड़ युक्त पानी भरा रहता है। स्थानीय बच्चे वहीं शौच करते हैं और जानवर भी विचरण करते हैं। इस संबंध में बीएसए व ईओ को पत्र भेजा गया है, जिससे परिसर के आसपास साफ-सफाई हो सके। नगर पंचायत की ईओ सृष्टि सिंह ने कहा कि प्रकरण संज्ञान में आया है। दो से तीन दिन में गंदगी व कूड़ा-करकट साफ करवा दिया जाएगा।

साहित्य संगम संस्थान उत्तर प्रदेश इकाई ने मनाया अपना पंचम वार्षिकोत्सव

नई दिल्ली। साहित्य संगम संस्थान उत्तर प्रदेश इकाई ने अपना पंचम वार्षिकोत्सव शनिवाद को बहुत ही धूमधाम से काव्य मंच पर मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश शर्मा पुरोहित रहे। सारस्वत अतिथि डॉ लवकुश तिवारी माधवपुरी, सम्मानित अतिथि डॉ छगनलाल गर्ग विज्ञ, देव अतिथि गणेश चंद्र केष्टवाल रहे। कार्यक्रम का संयोजन व संचालन डॉ राजीव रंजन मिश्र ने किया। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ डॉ राजीव रंजन मिश्र द्वारा शंखनाद से शुरू हुआ। डॉक्टर लवकुश तिवारी माधवपुरी जी द्वारा मां सरस्वती की आराधना की गई। तत्पश्चात डॉ राजीव रंजन मिश्र जी द्वारा गणेश वंदना की गई। फिर नरेश द्विवेदी के द्वारा गुरु वंदना की गई। इकाई की उपाध्यक्ष प्रतिभा पाण्डेय द्वारा अतिथियों व साहित्यकारों का स्वागत किया गया। देश के कोने-कोने से साहित्यकारों ने अपनी अपनी बधाइयां व शुभकामनाएं प्रेषित की। इकाई की पंच परमेश्वरी अनुराधा प्रियदर्शनी, नीता शेखर, इकाई की योजना सचिव सरिता सिंह, रविन्द्र वर्मा, प्रमाण अधिकारी प्रीति द्विवेदी ने बढ़चढ़ अपना योगदान दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह मंत्र की परिकल्पना दिन दूनी रात चौगुनी पुष्पित व पल्लवित हो रही है। साहित्य के प्रति आपका अनुराग अनुकरणीय है। आज के भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि साहित्य संगम संस्थान उत्तरप्रदेश इकाई द्वारा प्रतिदिन साहित्यिक गतिविधियां आयोजित की जा रही है साथ ही रचनाकारों को सम्मानित भी किया जाता है। कार्यक्रम में राम प्रकाश अवस्थी रूह, गौतम सिन्हा, मंजुषा किंजवडेकर, प्रीति द्विवेदी, श्रीकांत तैलंग, बृज व्यास, डॉ भावना दीक्षित, प्रमोद पाण्डेय, राजेश कुमार कौरव, दिनेश मिश्र, रंजना बिनानी ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम के अंत में इकाई अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्र मधुब्रत ने समस्त साहित्यकारों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

तेज धूप का बढ़ा प्रकोप, बढ़े चर्मरोगी



संतकबीरनगर। पिछले चार दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी ने और चिलचिलाती धूप ने त्वचा पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया है। तेज धूप के कारण त्वचा झुलसने के साथ ही शरीर पर लाल चकत्ते और काले धब्बे पड़ रहे हैं। कई लोगों को जलन और हाथ-पैरों में छोटे लाल दाने निकलने की शिकायत भी हो रही है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन ऐसे 40 से 50 मरीज त्वचा संबंधी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सक इलाज के साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। जैसे ही तेज धूप का प्रकोप बढ़ा है, चर्म रोगियों की संख्या में भी तेजी आई है। लोग फंगल इंफेक्शन सहित अन्य त्वचा संबंधी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिससे उन्हें खुजली और चेहरे पर काले धब्बे जैसी परेशानियां हो रही हैं। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. एसबी गौतम के अनुसार, ये समस्याएं मुख्य रूप से तेज धूप और अत्यधिक पसीने के कारण हो रही हैं। उन्होंने बताया कि यह एक संक्रामक स्थिति भी हो सकती है, जो पसीने से पनपती है। यह रोग अक्सर उंगलियों के बीच, बगल, कलाइयों, जांघों, पीठ और अंदरूनी हिस्सों में होता है। बार-बार खुजली करने से प्रभावित अंगों पर लाल दाग पड़ जाते हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि परिवार का एक सदस्य प्रभावित होता है, तो अन्य सदस्यों के भी इस संक्रमण की चपेट में आने का खतरा रहता है। इसलिए, सभी को सावधानी बरतने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी गई है।



चीन अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है और इसे दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में' इस राज्य पर अपना अनैतिक दावा जाता है। जबकि चीन भली भांति जानता है कि नाम बदलने से कुछ खास होने वाला नहीं है। चीन ऐसी हरकत 2017, 2021, 2023, 2024 और अब 2025 में कर रहा है। चीन ये नाम मंदारिन तिब्बती था फिर पिनियन भाषाओं में देना है। चीन जब भारत भी भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुतबा स्थापित हो रहा होता है, तब रुतबे को आहत करने की हीन भावना से यह हर करत करता है।

चीन की हरकत: पड़ोसी देशों की संपत्ति हड़पना

भारतीय मिसाइलों में सुरक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने ड्रोनों के माध्यम से जो मिसाइलें भारतीय क्षेत्रों में दागीं' उन्हें वायु, सैनिकों द्वारा छोड़ी गई ब्रहमोस और आकाश मिसाइलों ने आसमान में ही नाकाम कर दिया था। चीन को पाकिस्तान के पक्ष में सीधी उपस्थिति के भारत में चीन के सरकारी मुखराम ग्लोबल टाइम्स और सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के एक्स खाते भारत में बंद कर दिए। ग्लोबल टाइस में आपरेशन सिंदूर के दौरान अनेक मन गढ़न्त खबरें छापीं और झूठे दावे भी किए थे। सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब हाल में भारत सरकार ने पाकिस्तान के एक्स हैंडल के खिलाफ भी ऐसी ही कारवाई की है। साथ ही भारत ने तुर्किए के साथ भी अनेक व्यापारिक समझौते तोड़ते हुए पर्यटकों के वहां जाने पर रोक लगा दी। चीन को हमेशा कुटिल निगाहें वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को लांघने की भी रही है। चीन ने 15 जून 2020 को लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र गलवान में घाटी में सीमा उल्लंघन का प्रयास किया था जिसके चलते भारत और-चीन की सेनाओं के बीच झड़पें भी हुई थीं जिसमें करीब 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। चीन के भी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे लंबे समय के गतिरोध के बाद चीन नियंत्रण रेखा से पीछे हटने को मजबूर हुआ था। यहां मार खाने के बावजूद चीन का अरुणाचल में हस्तक्षेप का प्रयास निरंतर बना हुआ है। 1962 के युद्ध के समय-चीन ने भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में अपने सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी तवांग के रास्ते असम तक पहुंचायी थी। भारत, चीन की इस चालाकी से अच्छी तरह से परिचित है। अतएव पिछले एक दशक में समूचे अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रगत विकास को बहुत तेज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस विकास को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। चीन के लिए यह विकास और भारत सरकार का दो टूक जबाब परेशानी का सबब बन रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लगे सीमाई इलाकों में 63 सड़कें भारत सरकार बना रही है। इनमें से कई जगह सड़कें व पुल तैयार होने के साथ आवागमन के लिए भी खोल दिए गए हैं। नतीजन भारतीय सैनिकों को सीमा तक पहुंच आसान हो गई है।

सनद रहे कि - 1962 में सड़कें नही होने के कारण ही भारतीय सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। चीन की घुसपैठ रोकने के लिए तवांग समेत अरुणाचल के अन्य सीमा क्षेत्र में भारत ने अपने सैनिकों की संख्या और हथियारों के जखीरे बढ़ा दिए हैं। इसलिए चीन जिस रास्ते घुसने की कोशिश करता है, उसे सेना तत्काल माकूल जवाब दे देती है। हालांकि चीन की तरफ से भी अपने इलाके में लगातार सड़के पुल और सैनिक अड्डे बनाए जा रहे हैं।

चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थलों को चीनी नाम दे दिए तीन अरुणाचल में हरकतें पहले भी कर चुका है। कुंठित तानाशाह अपनी विचलित मानसिकता संतुष्ट करने के लिए अक्सर ऐसी ही हरकतें करते हैं। चीन की यह कुंठा इसलिए जागृत हुई क्योंकि भारतीय वायु सेना ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद करने के लिए ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें दागीं तो चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गई प्रतिरक्षा प्रणाली खोखली साबित हुई। इससे चीन के घटिया हथियारों की पोल डिजिटल साक्ष्यों के साथ पूरी दुनिया के सामने सार्वजनिक हो गई। परिणामस्वरूप उसके आयुध बजार को जबरदस्त झटका लग गया । मिसाईल निर्माण करनेवाली चीनी कंपनीयों के शेयर जमीन पर आ गए। चीन की यह बचकानी हरकत है कि जब भी भारत को ई बड़ा काम करता है तो चीन पूर्वोत्तर क्षेत्रके इस भारतीय प्रांत में ग्रामों, नगरों, नदियों और पहाड़ों के नाम चीनी भाषा मंदारिन में रख देता है और बाकायदा बाकायदा आधिकारिक बयान अपनी सरकारी वेब साइट ग्लोबल टाइस पर कर देता है। चीन के प्रपंच की यह आदत आभासी या छद्म युद्ध छेड़ने जैसी बार-बार सामने अति रहा है। लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आता है। इस हरकत के सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने देखा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थलों के नाम बदलने का खोखला एवं निरर्थक काम किया है। अपने पारंपरिक सैद्धांतिक नीति को जारी रखते हुए हम इस तरह को कोशिशों को सिरे से खारिज करते हैं। नाम बदलने की थोथी प्रक्रिया से जमीन पर वास्तविकता नहीं बदल जाती है। अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। चीन ने ऐसी ही हरकत अरुणाचल प्रदेश में तब की भी-जब 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस प्रदेश की 1300 फीट की ऊंचाई पर निर्मित की गई सेला सुरंग का उद्घाटन करने पहुंचे थे। तब अरुणाचल के तीस स्थानों को नए नाम देने की हरकत की थी।

डोकलाम विवाद के बद से ऐसी हरकते लगातार सामने आती रही है। 2017 में जब दलाई लामा अरुणाचल पहुंचे थे, तब भी तीन ने नाम बदले थे। इन नामों की सूची -बीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी प्रकाशित की जाती है। चीनी नागरिक मामलों का मंत्रालय इन सूचियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ही डालता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है और इसे दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में' इस राज्य पर अपना अनैतिक दावा जाता है। जबकि चीन भली भांति जानता है कि नाम बदलने से कुछ खास होने वाला नहीं है। चीन ऐसी हरकत 2017, 2021, 2023, 2024 और अब 2025 में कर रहा है। चीन ये नाम मंदारिन तिब्बती था फिर पिनियन भाषाओं में देना है। चीन जब भारत भी भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुतबा स्थापित हो रहा होता है, तब रुतबे को आहत करने की हीन भावना से यह हर करत करता है। भारत में जब 9-10 दिसंबर-2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन नईदिल्ली में आयोजित किया, तब इस सम्मेलन को एक बैठक अरुणाचल में संपन्न हुई थी। तब-तीन ने अरुणाचल में खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे जैसी हरकत दिखाई थी। उस सम्मेलन में चीन शामिल नहीं हुआ था। चीन ने अरुणाचल क्षेत्र में अवैधानिक रूप से गांव बसाने के भी प्रयास किये हैं। चीन अपने मानचित्रों में अरुणाचल को अपना बताने की कोशिश करता रहा है। चीन की ये हरकतें उसकी विस्तारवादी नीति की कुटिल एवं नापाक इच्छाएं दर्शाती हैं। वर्तमान परिपेक्ष्य में देखें तो साफ है कि- पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी आतंकवाद के विरुद्ध आपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो चीन और तुर्किए खुले रूप में पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए थे। यही नहीं चीन ने पाकिस्तान को वायु सुरक्षा प्रणाली और ड्रोन दिये थे। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के शिखर क्षेत्र त्सारी चू में गांव बसाने की कोशिश भी हुई थी। तिब्बत के दक्षिणी क्षेत्र जंगनान से जुड़ी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। चीन ने प्रमुखतापूर्वक कहा है कि जंगमान क्षेत्र (जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है) है। उसके साथ अरुणाचल प्रदेश के अस्तित्व को भी कोई मान्यता नहीं देता है। अर्थात अरुणाचल को चीन विवादित क्षेत्र जानकर चल रहा है। कुछ साल पहले चीन में ने अरुणाचल में वास्तविक सीमा के करीब 4.5 किमी अंदर घुसकर 101 नये घर बना कर एक पूरा गांव बसा लिया था। यह गांव अरुणाचल के सुबनसिरी जिले में था। इस गांव के बसाये जाने का रहस्य का खुलासा उपग्रह से ली गई तस्वीरों से हुआ था। ये तस्वीरें एक नवंबर, 2020 की बताई गई थी।

चीन से दो टूक बात करने वक्त

भारत और चीन के रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत की बहादुर सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बात करना जरूरी है। भारत के सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल 59 नेताओं और पूर्व राजनयिकों ने 33 देशों की यात्रा से वापस लौटने के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत के इस प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश की। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और आतंकवाद, एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से लेकर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी सहित कई नेता यह स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहा है। अमेरिका की यात्रा पर गए बिलावल भुट्टो जरदारी का एक और बयान काफी चर्चा में है जिसमें आतंकवाद का ठीकरा उन्होंने अमेरिका पर ही फोड़ दिया है। पाकिस्तान, अमेरिका और आतंकवाद इन तीनों के आपसी संबंधों की कहानी किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आ-सिफ ने हाल ही में स्काई न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान बस अमेरिका की भूमिका पर फिर से मुहर लगाने का काम कर दिया था। ख्वाजा आसिफ के शब्दों पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि, हम करीब तीन दशक से अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों के लिए यह गंदा काम (आतंक- वाद का समर्थन) कर रहे हैं। यह एक गलती थी और हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ी, इसीलिए आप मुझसे यह कह रही हैं। अगर हम सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में और 9/11 के बाद की जंग में शामिल नहीं होते, तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग होता।



अब पड़ोसी चीन से दो टूक भाषा में बात करने का समय आ गया है। चीन पाकिस्तान को हर तरह की ना केवल मदद मुहैया करा रहा है बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश होने के नाते आतंकवादी संगठनों, आतंकवादियों और पाकिस्तान के लिए ढाल का काम भी कर रहा है।

जहां तक अमेरिका की बात है, वहां के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैए से उसकी पोल लगातार खुल रही है। पाकिस्तान पर एक के बाद एक अमेरिका जिस तरह की मेहरबानी कर रहा है, वह भी पूरी दुनिया देख रही है। लॉस एंजिल्स में जो कुछ हुआ उसके बाद अमेरिकी जनता को भी अहसास होने लगा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। भारत अमेरिकी संबंधों में मचे घमासान के बीच अब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने सीमाओं की सुरक्षा और पड़ोसी देशों से बेहतर तालमेल स्थापित करना होना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब पड़ोसी चीन से दो टूक भाषा में बात करने का समय आ गया है। चीन पाकिस्तान को हर तरह की ना केवल मदद मुहैया करा रहा है बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश होने के नाते आतंकवादी संगठनों, आतंकवादियों और पाकिस्तान के लिए ढाल का काम भी कर रहा है। चीन पाकिस्तान के बाद श्रीलंका, म्यामांर , बांग्लादेश और नेपाल के सहारे भी भारत की घेरेबंदी कर रहा है। आखिर भारत इसे कब तक बर्दाश्त कर सकता है ?

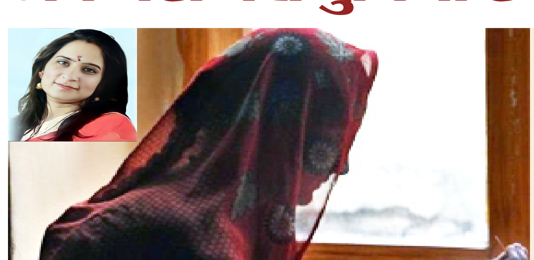
बताया जा रहा है कि, चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईडोंग इस सप्ताह भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। इस साल दोनों देशों के बीच यह दूसरी उच्चस्तरीय यात्रा होगी। इससे पहले, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी जनवरी में चीन की यात्रा पर गए थे। वहां सुन और मिसरी ने आपसी रिश्तों को सामान्य करने के लिए कई मुद्दों पर सहमति जताई थी। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। उसके बाद से अब माहौल काफी बदल गया है। भारतीय बाजार के बल पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाले चीन से अब यह तो पूछा ही जाना चाहिए कि वह पाकिस्तान के रास्ते पर क्यों चलना चाहता है ? पाकिस्तान तो आतंकवाद को पालते-पालते एक असफल देश बन चुका है लेकिन चीन जैसे बड़े देश की आखिर क्या मजबूरी है कि उसे आतंकवादियों का साथ देना पड़ रहा है। भारत और चीन के बीच आपस में विवाद है, यह एक कड़वी सच्चाई है लेकिन दुनिया के दो प्रभावशाली और बड़े देश होने के नाते इसे सुलझाने के कई तरीके हो सकते हैं। बातचीत से अगर ये मामले सुलझ जाए तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता लेकिन क्या चीन की सेना इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब उसे भी भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान जैसे नाकाम देश और आतंकवादियों का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है ? वक्त आ गया है कि भारत को अब दो टूक शब्दों में चीन से इन सवालों का जवाब मांगना ही चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ही यह कह चुके हैं कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की यह नीति सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं अपनानी चाहिए बल्कि हर उस देश के साथ अपनानी चाहिए जो किसी भी सूरत में आतंकवादियों का बचाव करता है। भारत को यह कठोर संदेश भारत यात्रा पर आने वाले चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईडोंग के जरिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक भेजना ही चाहिए।

केंद्र सरकार के उपक्रम बन रहे कमाऊ पूत

आज से एक दशक से अधिक समय पूर्व तक केंद्र सरकार के उपक्रमों को चलायमान बनाए रखने के लिए केंद्रीय बजट में भारी भरकम राशि का प्रावधान करना पड़ता था तथा इन उपक्रमों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। परंतु, आज स्थिति एकदम बदल गई है एवं अब केंद्र सरकार के उपक्रम केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में भारी भरकम राशि प्रदान कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लाभ अर्जित किया है। केंद्र सरकार के उपक्रमों में यह आमूलचूल परिवर्तन केंद्र में ईमानदार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा निगमित अभिशासन से सम्बंधित नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के चलते ही सम्भव हो सका है। पूर्व में इन उपक्रमों में पनप रहे भ्रष्टाचार के चलते इन उपक्रमों की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ता था परंतु अब उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगभग पूर्णतः अंकुश लगाया जा चुका है। साथ ही, केंद्र सरकार के इन उपक्रमों को नेतृत्व प्रदान कर रहे अधिकारियों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता रहा है। केंद्र सरकार के इन उपक्रमों में आज का नेतृत्व कुशल, ईमानदार एवं देश प्रथम की नीति पर चलने के साथ ही देश के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला है।

वित्तीय वर्ष 2024 में केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लाभ अर्जित किया है। प्रथम स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक है, जिसने 67,085 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। इसके बाद ओएनजीसी ने 49,221 करोड़ रुपए, आईओसी ने 41,730 करोड़ रुपए, भारतीय जीवन बीमा निगम ने 40,916 करोड़ रुपए, भारतीय कोयला निगम ने 37,402 करोड़ रुपए, बीपीसीएल ने 26,859 करोड़ रुपए, एनटीपीसी ने 20,812 करोड़ रुपए, बैंक आफ बड़ोदा ने 18,767 करोड़ रुपए, हिन्दुस्तान पेट्रोलीयम ने 16,015 करोड़ रुपए एवं पावर फाइनैन्स करपोरेशन ने 15,889 करोड़ रुपए की राशि का लाभ अर्जित किया है। इसके अतिरिक्त, पावर ग्रिड, कनारा बैंक, आरईसी लिमिटेड एवं यूनियन बैंक, ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लाभ अर्जित किया है। साथ ही, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, इंडीयन बैंक, जैसे केंद्र सरकार के 42 अन्य उपक्रमों ने भी भारी भरकम राशि का लाभ अर्जित किया है। केंद्र सरकार के उपक्रमों के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत में एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है एवं इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण लगभग नहीं के बराबर रहता है, ने भी पूरे विश्व के कई बड़े केंद्रीय बैंकों के बीच सबसे अधिक राशि का लाभ अर्जित किया है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व को वर्ष 2024 में 7,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है, इसी प्रकार ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक, बैंक आफ इंग्लैंड को 4 हजार करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुक्सान हुआ है तथा यूरोपीयन यूनियन के केंद्रीय बैंक, ईसीबी को 900 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुक्सान हुआ है। वहीं, इन केंद्रीय बैंकों की तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,100 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लाभ हुआ है। जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को इस वर्ष 2.70 लाख करोड़ रुपए की राशि का लाभांश अदा करने की घोषणा की है। विभिन्न केंद्र सरकार के उपक्रमों ने भी इस वर्ष केंद्र सरकार को भारी भरकम राशि का लाभांश अदा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्र सरकार के उपक्रमों से प्राप्त होने वाली कुल लाभांश की राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट में किए गए प्रावधान की राशि से कहीं अधिक है। इसी प्रकार, केंद्र सरकार को प्रत्येक माह प्राप्त होने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि भी अब मासिक औसत के रूप से 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। अप्रेल 2025 माह में तो केंद्र सरकार को रिकार्ड 2.36 लाख करोड़ रुपए की राशि का राजस्व वस्तु एवं सेवा कर की मद से प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार, मई 2025 में 2.01 लाख करोड़ रुपए की राशि का राजस्व जीएसटी मद से प्राप्त हुआ है। देश में प्रत्यक्ष कर (आय कर एवं कारपोरेट कर सहित) के रूप में प्राप्त राशि अप्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त राशि से कहीं अधिक रही है। देश के आम नागरिकों के हित में यह बहुत अच्छा कार्य हुआ है क्योंकि प्रत्यक्ष कर उन नागरिकों से प्राप्त किया जाता है जो इस कर को अदा कर सकने की क्षमता एवं योग्यता रखते हैं अर्थात उनकी आय कर देने योग्य आय के स्तर से ऊपर रहती है जबकि अप्रत्यक्ष कर समाज के प्रत्येक वर्ग पर सामान्य रूप से एक जैसा लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22.26 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रत्यक्ष कर के रूप में केंद्र सरकार को प्राप्त हुई थी जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त 19.60 लाख करोड़ रुपए की राशि से 13.57 प्रतिशत अधिक है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अप्रत्यक्ष कर (जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क शामिल हैं) के रूप में प्राप्त राशि का लक्ष्य 16.33 लाख करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया था। अप्रत्यक्ष कर की मद की तुलना में प्रत्यक्ष कर की मद से अधिक कर राशि का संग्रहण होना यह भी दशार्ता है कि भारत में नागरिकों की कर देने योग्य आय में वृद्धि दर अधिक है एवं आय कर अदा करने वाले नागरिकों की संख्या में भी अतुलनीय सुधार हो रहा है।

अब यही मेरी दुनिया है: एक स्त्री की खामोश क्रांति



कुछ औरतें मायके के बिना जीना सीख जाती हैं —न माँ की गोद, न भाई का कंधा, फिर भी हर रिश्ता निभाती हैं। दुख पी जाती हैं, आँसू अपने आँचल से पोंछ लेती हैं। कोई नहीं कहता बेटी थक गई होगी, पर वह खुद को समझा लेती है कि यही अब उसकी दुनिया है। यह कोई हार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की चुपचाप क्रांति है।

स्त्री—वह शब्द जिसे कहते तो हम 'जननी', 'धैर्य की मूर्ति', 'संसार की आधारशिला' हैं, लेकिन जब वही स्त्री अपने अधिकार, सम्मान और भावनात्मक सहारे की बात करती है तो समाज उसे ह्यसहनशीलह्व बने रहने की सलाह दे डालता है। एक बेटी जब विदा होती है, तो उसके साथ भावनाओं की एक पूरी दुनिया भी उसकी ससुराल चली जाती है। पर क्या यह विदाई केवल भौतिक होती है? या एक गहरी मानसिक क्रांति की शुरूआत?

मायका: एक भावनात्मक स्मृति, न कि वापसी का ठिकाना

हर स्त्री का मायका उसके जीवन की पहली पाठशाला होता है। वहीं उसने चलना, बोलना, हँसना, डरना और दुनिया को देखना सीखा। पर एक बार विवाह के बाद, वही मायका धीरे-धीरे 'अतीत' बन जाता है। अब वह 'बेटी' नहीं, 'बहू' होती है। उसे मायके जाना 'ज्यादा नहीं शोभा देता'। वहाँ के दुःख में वह 'मेहमान' बन जाती है और अपने ही घर में 'अजनबी'।

वह जानती है कि अब वह कभी उस गोद में सिर नहीं रख सकती जिसे कभी माँ की ममता कहा जाता था। अब उसके आँसू पोछने के लिए भाई की बाँह नहीं है। अब वह किसी को नहीं कह सकती कि ₹मैं थक गई हूँ₹, क्योंकि अब उसे ही सबको संभालना है।

रिश्तों में ज़िम्मेदारी, पर दिलचस्पी की कमी

वह हर रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाती है। चाहे सास का मान हो या पति की सेवा, बच्चों की परवरिश हो या घर की हर छोटी-बड़ी ज़िम्मेदारी—वह सब कुछ करती है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसके अपने सपने, इच्छाएँ और भावनाएँ धीरे-धीरे बेमानी हो जाती हैं।

रिश्तों में दिलचस्पी की जगह अब जरूरतें रह जाती हैं। अब वह बहू है, माँ है, पत्नी है, लेकिन शायद 'बेटी' अब सिर्फ एक स्मृति बन चुकी है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह मुस्कुराती रहे, चाहे भीतर कितनी ही आँधियाँ क्यों न चल रही हों।

चुप्पी: एक हथियार या हार?

जब कोई कहता है, 'बेटी थक गई होगी,' तो एक मौन गूंजता है—न कोई आवाज, न कोई शिकायत। क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी थकान का कोई मोल नहीं। वह आँसू भी अपने आँचल से ही पोंछ लेती है और खुद को समझा लेती है, 'अब यही मेरी दुनिया है।'

यह चुप्पी हार नहीं है, यह एक हथियार है—संघर्ष का, संयम का, और शायद क्रांति का भी। यह वही चुप्पी है जो स्त्रियों को सहने की नहीं, समझने की शक्ति देती है। यह चुप्पी उन्हें टूटने नहीं देती, बल्कि उनके भीतर एक औरत से 'नायिका' बनने की प्रक्रिया को जन्म देती है।

जब 'घर' ही पराया हो जाए

स्त्रियाँ उस घर को 'अपना' मान लेती हैं, जहाँ उन्हें केवल भूमिका निभानी होती है। अपने मन की बात कहने की जगह नहीं होती, बस जिम्मेदारियों का पहाड़ होता है। ऐसे में अगर किसी दिन वह सिर्फ इतना कह दे कि 'मुझे भी थोड़ी देर बैठना है', तो घर में खलबली मच जाती है।

उसे हमेशा दूसरों के सुख में खुश होना सिखाया गया है। खुद के दुःखों को जीने की इजाजत नहीं। वह घर की लक्ष्मी तो बनती है, पर मन की रानी शायद ही कभी।

आत्मनिर्भरता की अनसुनी कहानियाँ

हम कहते हैं कि औरतें आज आत्मनिर्भर हो गई हैं। वे ऑफिस जाती हैं, पैसा कमाती हैं, निर्णय लेती हैं। पर क्या मानसिक रूप से उन्हें वह स्पेस, वह सुरक्षा, वह 'अपनेपन' का वातावरण मिला है?

वह बिना मायके के भी जीना सीख गई है। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा का सार है। वह जानती है कि अब किसी का कंधा नहीं मिलेगा। वह अपने आँचल को ही तकिया बना लेती है और अपनी पीठ खुद थपथपा लेती है।

क्या सिर्फ बहू बनकर जीना जरूरी है?

स्त्री को एक बहू, पत्नी या माँ बनकर जीने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि वह एक 'व्यक्ति' के रूप में क्या चाहती है? उसकी भावनाएँ, इच्छाएँ, सपने – क्या वो सबकुछ शादी के साथ खत्म हो जाने चाहिए? विवाह उसके जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सम्पूर्ण नहीं। वह एक पूरी किताब है, जिसे अक्सर केवल एक पृष्ठ पढ़कर ही समाज तय कर देता है कि वह कैसी स्त्री है।

समाज को स्त्रियों की चुप्पी सुननी होगी

यह लेख किसी एक स्त्री की नहीं, बल्कि अनगिनत स्त्रियों की कहानी है जो अपने आँचल से आँसू पोछकर मुस्कराती हैं। समाज को यह चुप्पी सुननी होगी। यह कोई मौन नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फूट सकता है। जब स्त्रियाँ कहती हैं, ₹अब यही मेरी दुनिया है,₹ तो यह कोई संतोष नहीं, बल्कि एक ऐसा आत्मनिर्भर संघर्ष है, जिसमें उसने खुद को एक नई दुनिया मान लिया है – बिना शिकायत, बिना समर्थन, बिना अपेक्षा।

समाप्ति नहीं, शुरूआत है ये...

स्त्रियाँ जब चुपचाप घर संभालती हैं, दुख छुपा लेती हैं, हँसी ओढ़ लेती हैं, तो समाज समझता है कि उन्होंने हार मान ली। लेकिन सच्चाई यह है कि यह चुप्पी किसी अंत की नहीं, बल्कि एक नई शुरूआत की भूमिका होती है। जब एक स्त्री मायके के बिना भी जीना सीख जाती है, तो समझिए उसने अपने भीतर एक नई दुनिया बसा ली है। वह अब न बेटी रही, न बहू – वह अब केवल एक औरत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर अस्तित्व है।

-प्रियंका सौरभ



अंधकार के बीच उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। असम की बीरूबाला राभा ने इसी प्रथा के खिलाफ अकेले मोर्चा खोला था। उन्होंने अपना पूरा जीवन डायन प्रथा के खिलाफ संघर्ष में झोंक दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और असम में इसके खिलाफ कानून बना।

कानून के बूते महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को नहीं रोका जा सकता

बिहार में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को डायन होने के आरोप में गांव वालों ने घसीटा, पीटा और मैला पिलाने की कोशिश की। यह घटना अंधविश्वास और डायन प्रथा की वजह से हुई, जो बच्चों की बीमारी का दोष महिला पर मढने के लिए की गई। देश के राज्यों में ऐसी घटनाएं निजी दुश्मनी या संपत्ति हड़पने के लिए आम हैं। मानवता को कलंकित करने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बना है किन्तु ऐसे कानूनों का भी वही हाल है, जैसा निर्भया बलात्कार कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का हुआ है। निर्भया मामले के बाद फांसी तक प्रावधान किया गया, इसके बावजूद देश में ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे जाहिर है कि सिर्फ कानून के बूते महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को नहीं रोका जा सकता।

मुजफ्फरपुर की यह वारदात डायन प्रथा की कोई इकलौती घटना नहीं है। झारखंड, बिहार, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आज भी डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। परिवार की सम्पत्ति हड़पने की साजिश में, कभी निजी दुश्मनी में, तो कभी महज बीमारी और अनहोनी के लिए एक बलि का बकरा खोजने के बहाने के रूप में महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। क्रूरता के कलंक की यह कथा भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा सहित कई राज्यों में कानूनी प्रावधानों को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ जारी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2022 के आंकड़े इस अमानवीय सच्चाई की केवल एक झलक दिखाते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में डायन प्रथा के नाम पर देशभर में 85 हत्याएं दर्ज हुईं। लेकिन जो दर्द पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाता, उसकी संख्या कहीं अधिक है। कई पीड़ित महिलाएं तो कभी पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पातीं। डर, समाज का दबाव और अक्सर पुलिस की अनदेखी, इस काली गिनती को अधूरा छोड़ देती है। एनस-ीआरबी के 2014 में आंकड़े के मुताबिक झारखंड में 2012 से 2014 के बीच 127 महिलाओं की हत्या डायन बताकर कर दी गई। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री एचपी चौधरी ने ये आंकड़े बताए थे। वर्ष 2022 में ऐसे अपराधों में कमी आई है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म होने में शायद अभी भी दशकों लग जाएं। यह समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (2021) की रिपोर्ट बताती है कि 2009 से 2019 के बीच विश्व के 60 देशों में करीब 20,000 ऐसी घटनाएं सामने आईं, जहां लोगों को डायन बताकर प्रताड़ित किया गया। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओडिशा के 30 जिलों में से 12 जिलों, विशेषकर मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, मलकानगिरी, गजपति और गंजम- में डायन-शिकार अभी भी अत्यधिक प्रचलित है। इस तरह की अंधविश्वासी प्रथाओं के ज्यादातर शिकार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या फसल खराब होने के कारण होते थे। अध्ययन के अनुसार, लगभग 27 प्रतिशत मामले बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण, 43.5 प्रतिशत वयस्क परिवार के सदस्य की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, 24.5 प्रतिशत दुर्भाग्य या जमीन हड़पने के कारण और 5 प्रतिशत फसल खराब होने के कारण होते हैं। इस खौफनाक कुप्रथा की सबसे बड़ी शिकार महिलाएं बनती हैं। खासकर वे जो विधवा हैं, अकेली हैं या मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रही हैं। समाज के बीमार हिस्से ने इन्हें हर अनहोनी का कारण मान लिया है। अगर किसी घर में कोई बीमार पड़ जाए, फसल खराब हो जाए या गांव में कोई अनजानी विपत्ति आ जाए, तो इन बेबस महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। अंधकार के बीच उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। असम की बीरूबाला राभा ने इसी प्रथा के खिलाफ अकेले मोर्चा खोला था। उन्होंने अपना पूरा जीवन डायन प्रथा के खिलाफ संघर्ष में झोंक दिया. उनकी मेहनत रंग लाई और असम में इसके खिलाफ कानून बना।

असम सरकार का दावा है कि इस कानून के प्रावधान दूसरे राज्यों के ऐसे कानूनों के मुकाबले कठोर हैं। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि महज कानून बना कर सदियों पुरानी इस कुप्रथा को खत्म करना संभव नहीं है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक जागरूकता जरूरी है। दिल्ली स्थित संगठन पार्टनर्सस फार ला इन डेवलपमेंट नामक एक संगठन ने अपने शोध में कहा कि डायन प्रथा की जड़ें पितृसत्तात्मक मानसिकता, आर्थिक झगड़ों, अंधविश्वास और दूसरी निजी और सामाजिक संघर्ष में छिपी हैं। ज्यादातर मामले पुलिस के पास ही नहीं पहुंचते। ऐसे में सरकारी आंकड़े इस भयावह समस्या की सही तस्वीर नहीं दिखाते। देश में डायन प्रथा कब से शुरू हुई, इसका कोई प्रामाणिक इतिहास तो नहीं मिलता लेकिन यह सदियों पुरानी है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में डाकन या डायन प्रथा कोई छह-सात सौ साल पहले से चलन में थी। इसके तहत अपनी जादुई ताकतों के कथित इस्तेमाल से शिशुओं को मारने के आरोप में महिलाओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी जाती थी। उस दौर में वहां हजारों औरतें इस कुप्रथा का शिकार हुई थीं। राजपूत रियासतों ने 16वीं सदी में कानून बना कर इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। वर्ष 1553 में उदयपुर में पहली बार इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था। बावजूद इसके यह बेरोक-टोक जारी रही। यह प्रथा असम के मोरीगांव जिले में फली-फूली। इस जिले को अब काले जादू की भारतीय राजधानी कहा जाता है। दूर-दराज से लोग काला जादू सीखने यहां आते हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2000 से 2016 के बीच देश के विभिन्न राज्यों में डायन करार देकर 2,500 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। उनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। इस मामले में झारखंड का नाम सबसे ऊपर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में वर्ष 2001 से 2014 के बीच डायन होने के आरोप में 464 महिलाओं की हत्या कर दी गई। उनमें से ज्यादातर आदिवासी तबके की थीं। लेकिन सामाजिक कार्यकताओं का दावा है कि एनसीआरबी के आंकड़े तस्वीर का असली रूप सामने नहीं लाते। डायन के नाम पर होने वाली हत्याओं की तादाद इससे कई गुनी ज्यादा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में डायन के खिलाफ लोगों की एकजुटता की वजह से ज्यादातर मामले पुलिस तक नहीं पहुंच पाते। डायन प्रथा हो या निर्भयाकांड, सरकारें कानून बना कर अपनी जिम्मेदारी को पूरा मान लेती हैं, जमीनी धरातल पर हकीकत में तस्वीर बदले या न बदले।

आई.टी सैक्टर, चिकित्सा, विज्ञान एवं तकनीक, प्रबंधन क्षेत्र, रॉकेट साइंस सहित विभिन्न क्षेत्रों ने भारत ने विश्व में अपना लोहा मनवाया है।

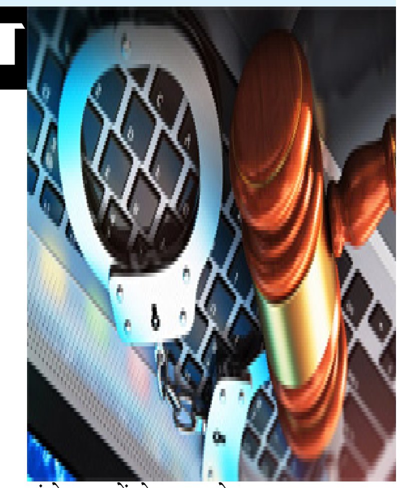
` विश्व की प्रमुख कंपनियों में से ज्यादातर के सीईओ भारतीय हैं। इसके बावजूद भारत में डायन जैसी कुप्रथा के मौजूद होने को यही माना जा सकता है कि असंतुलित विक-ास ऐसे कुरीतियों के लिए जिम्मेदार है। देश के विभिन्न राज्यों में डायन प्रथा के खिलाफ कानून होने के बावजूद अब तक इस सामाजिक कुरीति पर अंकुश नहीं लग सका है। गरीबी और विकास की बुनियादी सुविधाओं से वंचित इलाकों में ऐसे घटनाओं से जाहिर है कि असमानता चाहे जिस भी स्तर पर हो, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा तब तक विकास की तमाम सफलाताओं के बावजूद महिलाएं अत्याचार की चक्की में पिसती रहेंगी।

एक और खुश करने वाली रिपोर्ट

भारत एक ओर जहां लगातार तेज ग्रोथ करते हुए बीते दिनों जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना, तो वहीं उपलब्धियों का सिलसिला जारी है और दुनिया इसका लोहा मान रही है। अब एक और खुश करने वाली रिपोर्ट आई है, जो विश्व बैंक ने जारी की है, जिसमें भारत में अत्यधिक गरीबी में आई उल्लेखनीय कमी की रोशनी है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में यह दर 5.3 प्रतिशत रह गई है, जो वर्ष 2011-12 में 27.1 फीसदी थी। रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार भारत ने लगभग एक दशक से कुछ कम समय में 27 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है, जो पैमाने और गति के मामले में उल्लेखनीय एवं ऐतिहासिक उपलब्धि कही जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शासन के ग्यारह स्वर्णिम वर्षों में गरीबी को कम करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है, गरीबों के संघर्षों और उनकी चिंताओं को सुनकर, उन्हें गरीबी से बाहर आने में मदद करके और अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करके उन्होंने गरीब उन्मूलन की योजनाओं को जमीन पर उतारा है। मोदी सरकार ने गरीबी में रहने वाले लोगों और व्यापक समाज के बीच समझ और संवाद को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। उनकी दृष्टि में गरीबी को खत्म करना सिर्फ.गरीबों की मदद करना नहीं है - बल्कि हर महिला और पुरुष को सम्मान के साथ जीने का मौका देना है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही सरकारी पहलों, तेज आर्थिक सुधारों और जरूरी सेवाओं तक सबकी पहुंच का ही यह नतीजा है कि गरीबी दिन-ब-दिन तेजी से घट रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार रोजगार में वृद्धि हुई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में भी जबरदस्त प्रगति की है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2005-06 में 53.8 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 16.4 प्रतिशत और 2022-23 में 15.5 प्रतिशत हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर फोकस पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच को बढ़ाया है।

डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी), डिजिटल समावेश और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने अंतिम जन तक लाभों की पारदर्शिता और तेज वितरण सुनिश्चित किया है। इससे 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी पर पार पाने में मदद मिली है। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को संबल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और उनका बेहतर क्रियान्वयन किया है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34.44 करोड़ से घटकर 7.52 करोड़ रह गई है। पूरे भारत में अत्यधिक गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें प्रमुख राज्यों ने गरीबी में कमी लाने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पांच बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में 2011-12 में देश के 65 फीसदी अत्यंत गरीब लोग थे। इन पांच राज्यों ने ही 2022-23 तक गरीबी कम करने में दो-तिहाई का योगदान दिया है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारत से गरीबी उन्मूलन की योजनाओं एवं सोच से प्रेरणा लेने की बात कही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की 45 प्रतिशत आबादी गरीबी में है। भारत की गरीबी दर 5.3 प्रतिशत और पाकिस्तान की 42.4 प्रतिशत है। इसका सबसे बड़ा कारण पाक अपना सारा ध्यान आतंकवाद एवं आतंकवादियों के पोषण पर देता है, गरीबी दूर करना उसकी योजनाओं एवं नीतियों में दूर-दूर तक नहीं है। इसीलिये भारत ने वैश्विक मंचों पर पाक पर यह आरोप भी लगाया है कि वह अंतरराष्ट्रीय सहायता का दुरुपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। भारत ने विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे पाक को दी जाने वाली सहायता की समीक्षा करें, क्योंकि इसका उपयोग आम लोगों के कल्याण के बजाय सैन्य खर्च और आतंकवादी गतिविधियों में हो रहा है। हाल के पाहलगाम हमले के बाद भारत ने इस मुद्दे को और जोरदार तरीके से उठाया, जिसमें उसने पाक के सैन्य बजट में 18 प्रतिशत वृद्धि और सामाजिक कल्याण पर कम खर्च को उजागर किया। गरीबी किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन है। यह न केवल अभाव, भूख और पीड़ा का जीवन जीने की ओर ले जाती है, बल्कि मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के आनंद का भी बड़ा अवरोध है। पाक में यही स्थितियां देखने को मिल रही है। आजादी के अमृत काल में सशक्त भारत एवं विकसित भारत को निर्मित करते हुए गरीबमुक्त भारत के संकल्प को भी आकार दिया जा रहा है।

साइबर अपराध: एक विश्वव्यापी समस्या



देश दुनिया में साइबर अपराध के बढ़ते आंकड़े जहां चिंतित करने वाले हैं वहीं यह और भी आश्चर्यजनक और चिंताजनक हालात है कि लाख अवेयरनेस प्रोग्राम व मीडिया में आये दिन साइबर ठगी के समाचारों की भरमार के बावजूद देश में केवल 18 फीसदी लोग ही ऐसे हैं जिन्हें साइबर अपराध होने पर उसकी शिकायत कहां और कैसे करनी है कि जानकारी है। यह तो सरकारी आंकड़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जनवरी-मार्च, 2025 में कराए गए ताजातरीन सर्वे से यह आंकड़ें प्राप्त हुए हैं। दूसरी और यूपीआई से भुगतान में खासा बढ़ोतरी हुई हैं। आज ठेले पर सब्जी बेचने वाले से लेकर दो-पांच रुपए का सामान विक्रेता भी आसानी से यूपीआई से भुगतान प्राप्त कर रहा है। 2022-23 में जहां केवल 38 फीसदी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते थे वह आज बढ़कर 50 प्रतिशत के लगभग हो गया है। वास्तविकता तो यह है कि आज ऑनलाइन पेमेंट करना लोगों की आदत में आ गया है। जेब में रुपया-पैसा रखना या कहीं जाते समय साथ पैसा लेजाना लोगों की आदत में अब लगभग नहीं ही रहा है। पर तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद है और पिछले तीन सालों में ही साइबर अपराध के आंकड़ें तीन गुणा बढ़ गए हैं। सरकार की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आज मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करते ही पहले साइबर अपराध से सचेत रहने की कॉलर ट्यून सुनने को मिलती है और उसके बाद बात होती है।

मोबाइल पर नंबर मिलाते ही नहीं अपितु सोशियल मीडिया के प्लेटफार्म खासतौर से इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर आजकल साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन या ब्लेक मेलिंग से सतर्क रहने का संदेश सुनने को मिलता है। इतने के बावजूद ठगी के आंकड़ें चेताने वाले हैं। मजे की बात यह है कि साइबर ठगी के विभिन्न रुपों से सबसे अधिक शिकार पढ़े लिखे और समझदार लोग ही हो रहे हैं। लाख समझाइस के बावजूद एक और ठगों के हौसले बुलंद है तो ठगी के शिकार होने वाले लोगों की संख्या और राशि में मल्टीपल बढ़ोतरी हो रही है। खास बात यह है कि ठगी के केन्द्र व ठगी के तरीके से वाकिफ होने के बावजूद यह होता जा रहा है। हांलाकि झारखण्ड के जमातड़ा से ठगों के तंत्र को तोड़ दिया गया पर देश में एक दो नहीं अपितु 74 जिलों में इस तरह की ठगी करने वालों के हॉटस्पॉट विकसित हो गए। झारखण्ड, राजस्थान, हरियाणा और बिहार के केन्द्र पहले पांच प्रमुख सेंटर विकसित हो गए।

ऐसा नहीं है कि साइबर अपराध केवल और केवल भारत में हो रहे हैं अपितु यह विश्वव्यापी समस्या होती जा रही है। दुनिया के देशों में देखा जाए तो साइबर ठगी के मामलों में रशिया पहले पायदान तो यूक्रेन दूसरे स्थान पर है। इनके बाद चीन, अमेरिका, नाइजेरिया और रोमानिया का नंबर आता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है साइबर ठगों सारी दुनिया में सहज पहुंच है। लोगों की गाढ़ी कमाई को हजम करने में इन्हें विशेषज्ञता हासिल है। लोगों की कमजोरी को यह समझते हैं और उसी कमजोरी के चलते पढ़े लिखे और हौशियार लोगों को भी आसानी से ठगी का शिकार बना लेते हैं। जाल ऐसा की यह समझते हुए कि ऐसा आसानी से होता नहीं है फिर भी चक्कर में फंस ही जाते हैं और ठगों के आगे सरेण्डर होकर लुट जाते हैं। हमारे देश में साइबर ठग या तो किसी तरह का लालच देकर लिंक भेजकर ठगी करते हैं या फिर ड़रा धमकाकर आसानी से ठगी का शिकार बना लेते हैं। सरकार प्रचार के सभी माध्यमों से बार बार व लगातार आगाह कर रही है कि ठगों द्वारा ड़राने वाले तरीके वास्तविक नहीं है। बैंक कभी भी बैंक डिटेल या ओटीपी ऑनलाइन नहीं मांगते पर पता नहीं कैसे ठगों के जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई लुटा बैठते हैं। ओटीपी दे देते हैं तो लिंक खोलने के लिए लाख मना करने के बावजूद लिंक खोलकर लुट जाते हैं। पुलिस अधिकारी बन कर जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का रास्ता अपनाया जा रहा है उस संबंध में अवेयरनेस अभियान के बावजूद ठगी का शिकार होने वालों की संख्या या राषि में कमी नहीं हो रही है। डिजिटल अरेस्ट में डॉक्टर, रिटायर्ड जज, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी सहित संभ्रात वर्ग के लोगों को आसानी से जाल में फंसाकर ठगी हो रही हैं वह भी करोड़ों तक की ठगी के उदाहरण मिल रहे हैं। झूठे मामलों में परिजनों को फंसने से बचाने का झांसा देकर ठगी हो रही है। मजे की बात यह है कि इस स्तर तक ड़र या भयाक्रांत हो जाते हैं कि किसी अन्य या पुलिस से समस्या साझा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते और ठगी के बाद हाथ मलते रह जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामलें तो दिनोंदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दरअसल इसमें पुलिस, सरकारी जांच एजेंसी या प्रवर्तन निदेशालय के नकली अधिकारी बन कर इस कदर ड़रा देते हैं कि कई दिनों तक लगातार ऑडियो या वीडियो कॉल कर-के ठगी का शिकार बना लेते हैं।

ऐसा नहीं है कि सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। सरकार व वित्तदायी संस्थाओं द्वारा मीडिया के माध्यम से सजग किया जा रहा है। इसके साथ ही झारखण्ड के बड़े केन्द्र जमातड़ा को लगभग समाप्त कर ही दिया है। पर देष में 74 हॉट स्पॉट विकसित हो गए हैं। इनमें हरियाणा का नूंह, राजस्थान का डीग, झारखण्ड का देवघर, राजस्थान का अलवर और बिहार का नालंदा पहले पांच हॉट स्पॉट हो गए हैं। मीडिया द्वारा भी समय समय पर स्ट्रिंग कर इस तरह के केन्द्रों को एक्सपोज किया है पर ठगी कम होने को ही नहीं है। दरअसल आमनागरिकों को भी सजग होना ही होगा। अनजान नंबरों पर बात ही ना करें। ज्योंही कोई ड़राये धमकायें तो बहकावें में आने के स्थान पर पड़ताल करें। इस तरह के हालात सामने आये तो परेशान होने के स्थान पर परेशानी को साझा करें, पुलिस का सहयोग लेने में भी संकोच ना करें। देखा जाए तो सजगता इस समस्या का समाधान हो सकती है। सबसे ज्यादा जरुरी यह हो जाता है कि लाख सजगता के बावजूद भी यदि साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं तो उस स्थिति में बिना किसी घबराहट और संकोच के कहां ओर कैसे शिकायत की जा सकती है इसकी जानकारी देने के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ ही गैरसरकारी संगठनों को भी आगे आना होगा नहीं तो साइबर अपराध का जिस तरह से दायरा दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है उस पर अंकुश नहीं लग सकेगा।

फंगस केवल फसलों का ही दुश्मन नहीं, इंसानों की जान के लिए भी खतरनाक

विजय गर्ग

एक साइंस जर्नल के मुताबिक, फंगस कृषि आतंकवाद का खतरनाक हथियार हो सकता है। फ्यूजेरियम ग्रेमिनीअरम नामक एक फंगस विभिन्न अनाजों के विकास को प्रभावित करता है। इससे उपज भी कम हो जाती है। संक्रमित करने के बाद यह फंगस फसल के परिपक्व होने के साथ फैलता जाता है। फ्यूजेरियम ग्रेमिनीअरम छोटे अनाज के पौधों के तने और जड़ों के ऊतकों, अवशेषों में जीवित रहने और नये पौधों को संक्रमित करने के लिए जाना जाता है। यह माइकोटाक्सिन पैदा करता है जिसका सेवन हानिकर होता है।

बीते दिनों अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने मिशिगन यूनिवर्सिटी में शोधरत चीनी शोध वैज्ञानिक युनकिंग जियांग को गिरफ्तार किया जो अमेरिका में खतरनाक जैविक फंगस फ्यूजेरियम ग्रेमिनिअरम लेकर आई। वैसे फंगस विभिन्न तरह के रोग जैसे हेड ब्लाइट, रूट रौट व सीडलिंग ब्लाइट पैदा करता है। इसकी अधिकांश प्रजातियां मृदाकवक हैं। जबकि फ्यूजेरियम ग्रेमिनीअरम फंगस गेहूं, धान, मक्का और जौ में हेड ब्लाइट रोग फैलाता है। इससे मुख्यतः वोमिटोक्सिन पदार्थ पैदा होता है जो अनाज दूषित करता है। इससे निकले विषाक्त द्रव्य से हर साल अरबों डॉलर की फसल बर्बाद होती है व उपज कम होती है।

गौरतलब है कि एफबीआई ने पिछले साल जुलाई में चीनी शोध वैज्ञानिक जियान के ब्वायफ्रेंड लियू को उसके बैग में मिले लाल पौधे के पदार्थ के बारे में गोलमोल जवाब देने के बाद डेट्रायट हवाई अड्डे से वापस चीन भेज दिया था। लियू के मुताबिक, उसकी योजना मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब में अनुसंधान के लिए इस सामग्री का उपयोग करने की थी। इसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड जियान के जरिये छिपाकर इस खतरनाक फंगस को मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब तक पहुंचाया। लियू पहले इस लैब में काम करता था। फिलहाल वह चीनी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। एफबीआई निदेशक ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा है कि चीन अमेरिकी संस्थानों में घुसपैठ की साजिश कर रहा है ताकि खाद्य सुरक्षा तंत्र के जरिये बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस स्ट्रेन के अनधिकृत आयात से अधिक आक्रामक या कीटनाशक प्रतिरोधी वैरिएंट आने का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण नियंत्रण के उपाय कम प्रभावी होते हैं।

यह खतरनाक फंगस भारत में भी पाया जाता है। अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी आफ मेडिसिन की 2022 की रिपोर्ट की मानें तो उत्तर भारत में गेहूं की फसल में कई बार हेड ब्लास्ट के लक्षण देखे गये। हालांकि हर बार उस पर नियंत्रण पा लिया गया। इसके यहां सक्रिय होने के पीछे जलवायु परिवर्तन अहम कारण है। गेहूं की फसल के लिए इसे बड़ा खतरा माना जाता है। आईसीएआर के 2021 में हिमाचल और तमिलनाडु में किए व्यापक रोग- सर्वेक्षण में इस फंगस के बारे में खुलासा हुआ था। इससे गेहूं के दाने में हेड ब्लाइट या स्टैंड की समस्या हुई थी। यही नहीं 2021 और 2022 के बीच रबी सीजन में कर्नाटक कृषि विवि द्वारा किए एक सर्वे में कर्नाटक में हेड ब्लाइट की समस्या देखी गयी।

असल में अमेरिका में चीनी वैज्ञानिक द्वारा फ्यूजेरियम ग्रेमिनीअरम की तस्करी की घटना ने जहां वैश्विक कृषि सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं चेतावनी भी दी है कि इस तरह मिट्टी, बीज और फसलें भी आतंकवाद के हथियार बन सकते हैं। फ्यूजेरियम ग्रेमिनीअरम फंगस अनाज को सड़ा भी सकता है जिससे इंसान व मवेशियों की जान के लाले पड़ सकते हैं। बेहद सूक्ष्म होने के चलते यह आसानी से पकड़ में नहीं आता और हवा, मिट्टी और बीज के जरिये अपना विस्तार करता है। इसके शुरूआत में लक्षण फसली रोग जैसे होते हैं। इंसानों में जब तक इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। यह जैविक युद्ध का मौन हथियार साबित हो सकता है। वैज्ञानिक इसे ॒एग्रो टैररिज्म ॒ बता रहे हैं। फसलों को बर्बाद करने की खातिर जैविक एजेंट का इस्तेमाल कृषि आतंकवाद कहलाता है। जिसका मकसद अर्थव्यवस्था बर्बाद करना और समाज में भय-बिखराव का माहौल बनाना है।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 17 फीसदी से ज्यादा है और आधी से ज्यादा आबादी खेती से जुड़ी है, इसलिए भारत भी चीन के निशाने पर है। पंजाब, राजस्थान और हिमाचल राज्य चीन और पाकिस्तान से सटे हुए हैं और दोनों ही देश दुश्मन देश हैं। अब बांग्लादेश भी चीन-पाक की राह पर है। गौरतलब है कि 2016 में बांग्लादेश से ही भेजे गये जहरीले फंगस मैग्नपार्थ ओराइजा पाथोटायप ट्रिटिकम ने पश्चिम बंगाल के दो जिलों में तबाही मचाई थी। इस फंगस का जहर काफी खतरनाक है। यह मनुष्य के शरीर में दूषित भोजन (रोटी, अनाज, पास्ता, बीयर) से या प्रसंस्करण के दौरान, दूषित अनाज से धूल को सांस के माध्यम से त्वचा के संपर्क से प्रवेश करता है। मुख्यतः जठरांत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। इसके शिकार शिशु, बच्चे और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग होते हैं। इसके असर से इंसान को उल्टी, दस्त, बुखार, हार्मोनल असंतुलन, प्रजनन संकट, त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं पशुओं का विकास बाधित हो सकता है। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों में फफूंदरोधी गेहूं की उन्नत किस्मों पर अध्ययन जारी है,रोग प्रतिरोधक बीजों का ट्रायल किया जा रहा है लेकिन इसके साथ-साथ जैविक सुरक्षा मानकों व दिशा-निदेशों को सख्त बनाना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से निरंतर सहयोग-परामर्श, मौसम पूवार्नुमान प्रणाली और फफूंद का निगरानी तंत्र विकसित किया जाना बेहद जरूरी है तभी कुछ सीमा तक इस पर नियंत्रण संभव है।

मलोट पंजाब

बेमेल विवाह का दुष्परिणाम : सुपारी देकर मौत के घाट उतारने वाली स्त्री

समाज के बदलते परिवेश में बंदिशों की जगह नहीं रही है। यह गंभीर सामाजिक व पारिवारिक मसला बनता जा रहा है। इस पर गहन चिंतन की जरूरत है। विवाह पूर्व मैरिज काउंसलर व परिवार विशेषज्ञों की राय भी जरूरी है। अभी समाज दहेज हत्याओं से उबर नहीं पाया है कि यह नए तरह का संक्रमण दंपतियों को चपेट में ले रहा है। इस तरह की हत्या सोची-समझी साजिश का परिणाम होता है। मर्जी के बगैर विवाह या विवाह विच्छेदन को लेकर दायरे बदलने होंगे। सुपारी देकर मौत के घाट उतारने वाली स्त्री को माफ नहीं किया जाना चाहिए हत्या सिर्फ हत्या है। उसमें लैंगिक पक्षपात की कोई जगह नहीं है।



परिपक्व उम्र की लड़कियां घर के बड़ों के समक्ष जो आक्रोश व्यक्त नहीं कर पातीं, वह विवाह के उपरांत जानलेवा साबित होता नजर आ रहा है।

हनीमून के लिए मेघालय गई सोनम को पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। राजा व सोनम 23 मई से लापता थे। दो जून को राजा का शव खाई में मिला था, जबकि सोनम का लापता थी। पुलिस के अनुसार उसने भाड़े के हत्यारों के साथ मिलकर साजिश रची थी। 11 मई को दोनों की परिवार की मर्जी से शादी की हुई थी। 21 मई को दंपति शिलांग पहुंचा। राज कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान में काम करता था। जिसके साथ सोनम के रिश्ते थे। इन दोनों ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर बीस लाख रुपए में राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और पेड़.काटने वाली छोटी कुल्हाड़ी दाव ऑनलाइन मंगाई।

राजा की मां का कहना है, सोनम के विवाह में रुचि न लेने व फोन न सुनने से राजा उखड़ा-उखड़ा रहता था। मगर सोनम की मां का इस पर कहना था, उनका परिवार काफी सख्त है इसलिए उनकी बेटी अपने होने वाले पति के साथ मुलाकातें नहीं कर सकती। हनीमून की बुकिंग भी सोनम ने ही करवाई थी। शादी के बाद उसका बर्ताव ससुरालियों से अच्छा ही था। वह सबसे मिल-जुल कर रही और हनीमून के दरम्यान सबसे फोन पर बातें भी करती रही। सोनम के परिजन उसे बेगुनाह बता रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। परिवारों की मर्जी से शादी करने वाली नवविवाहिताओं में इस तरह का आवेश देखकर कहा जा सकता है कि परिजनों को अरेंज मैरिज को लेकर अपने विचार बदलने होंगे। जात-बिरादरी के बंधनों व आर्थिक स्तर को लेकर वैवाहिक संबंधों को बनाने की रवायतों में ढील लानी होगी। परिपक्व उम्र की लड़कियां घर के बड़ों के समक्ष जो आक्रोश व्यक्त नहीं कर पातीं, वह विवाह के उपरांत जानलेवा साबित होता नजर आ रहा है।

रिश्ते, भ्रम और हत्या इंदौर के राजा की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या, उसकी नवविवाहिता पत्नी द्वारा प्रेमी संग मिलकर की गई निर्मम साजिश, आधुनिक प्रेम की भयावह हकीकत बन गई। यह घटना न केवल व्यक्तिगत विश्वासघात है, बल्कि सामाजिक मूल्यों, भावनात्मक अपरिपक्वता और विवाह संस्थान की खोखली होती जा रही नींव का संकेत है। सनसनी के बजाय संवेदना जरूरी है। यह हत्याकांड रिश्तों की शिक्षा, संवाद और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर विमर्श की माँग करता है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, समाज के गिरते रिश्तों का आईना है।



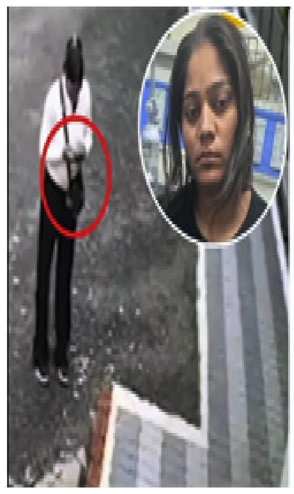
रिश्तों के लाश पर खड़ा आधुनिक प्रेम

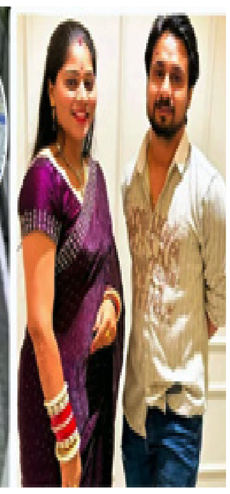
इंदौर के राजा और मेघालय की सोनम के हनीमून पर हुई हत्या की घटना न केवल व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि सामाजिक, नैतिक और मानसिक स्तर पर गहरी चिंता पैदा करती है। यह अपराध आधुनिक प्रेम और विवाह संबंधों में फैलते अविश्वास और स्वार्थ की भयावह तस्वीर पेश करता है। साथ ही, मेघालय जैसे पर्यटन स्थलों की छवि भी प्रभावित होती है। ऐसी घटनाएँ भावनात्मक शिक्षा, रिश्तों में पारदर्शिता और समाज के नैतिक मूल्यों की पुनर्समीक्षा की मांग करती हैं। भारत के सामाजिक परिदृश्य में प्रेम, विवाह और रिश्तों को पवित्र बंधन माना जाता रहा है। लेकिन जब हनीमून जैसी कोमल, सुंदर और विश्वास से भरी यात्रा हत्या का मंच बन जाए, तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं होता, यह पूरे समाज की अंतरात्मा पर चोट करता है। इंदौर के राजा और मेघालय की सोनम का हनीमून मर्डर केस केवल एक युवक की जान नहीं ले गया, उसने नॉर्थ ईस्ट की छवि को भी कलंकित किया, टूरिज्म सेक्टर पर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए और सबसे बड़ी बात – विश्वास की नींव पर टिके रिश्तों को ध्वस्त कर दिया।

इंदौर निवासी युवक राजा की शादी हाल ही में सोनम नामक युवती से हुई। नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने मेघालय पहुंचा। वहाँ की खूबसूरत वादियों, शांत झीलों और पहाड़ी रास्तों के बीच ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। हनीमून के बहाने सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम भी दे डाला। शुरूआत में राजा का गायब होना एक दुर्घटना माना गया। लेकिन जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, मोबाइल लोकेशन, चैट्स, बैंक ट्रांजैक्शन और सीसीटीवी फुटेज सामने आए, तब जाकर पूरी साजिश बेनकाब हुई।

सवाल यह है कि एक नवविवाहिता ऐसा क्यों करती है? जवाब आसान नहीं है, पर चिंतन जरूरी है। यह मामला केवल व्यक्तिगत धोखा नहीं, समाज की उस बनती मानसिकता का भी परिणाम है, जिसमें रिश्तों में धैर्य, संवाद और समर्पण की जगह जल्दबाजी, लालच और अवसरवाद ने ले ली है। सोनम पहले से एक अन्य युवक से प्रेम करती थी, और राजा से विवाह सिर्फ परिवार या आर्थिक मजबूरियों के चलते हुआ। लेकिन विवाह के बाद भी उसने उस प्रेमी को छोड़ा नहीं, बल्कि पति को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। आज के दौर में रिश्तों की शुरूआत इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से होती है, और अंत क्राइम पेट्रोल या पुलिस स्टेशन पर। भावनात्मक गहराई, एक-दूसरे को समझने का समय और परख की प्रक्रिया लगभग न के बराबर रह गई है।

विवाह को लेकर जिस जल्दबाजी और सामाजिक दबाव की संस्कृति बन गई है, उसमें युवक-युवती को खुद की इच्छाओं और संबंधों को समझने का समय ही नहीं मिलता। भावनात्मक अपरिपक्वता, आत्मकेंद्रित निर्णय और रिश्तों के प्रति गैर-जिम्मेदारी, इन सबका सम्मिलन इस हत्याकांड जैसी घटनाओं को जन्म देता है। यह घटना मेघालय के खूबसूरत पर्यटन स्थलों जैसे शिलॉग, चेरापूंजी, डावकी, उमगोट नदी आदि की छवि पर भी असर डाल गई। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे ह्लमेघालय हनीमून मर्डर केसह्व कहना शुरू कर दिया, जिससे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के प्रति अनावश्यक संदेह और डर का वातावरण बन रहा है। लेकिन प्रश्न यह है: क्या एक महिला की निजी आपराधिक साजिश





पूरे क्षेत्र को बदनाम कर सकती है? उत्तर है – नहीं। यह वही मानसिकता है जो किसी मुस्लिम अपराधी को देख पूरे धर्म पर टिप्पणी कर देती है, या किसी एक दलित व्यक्ति के कारण पूरी जाति को दोषी ठहराती है। यह सोच भी उतनी ही खतरनाक है जितनी खुद वह घटना। शादी अब समझौता नहीं, सौदा बन रही है। प्रेम अब समर्पण नहीं, स्वार्थ बन गया है। और भरोसा अब भावना नहीं, बिजनेस जैसा व्यवहार हो गया है। जिस तरह से सोनम ने योजनाबद्ध तरीके से पति की हत्या की, वह दिखाता है कि क्रूरता अब हथियार से नहीं, रिश्तों के माध्यम से भी हो रही है।

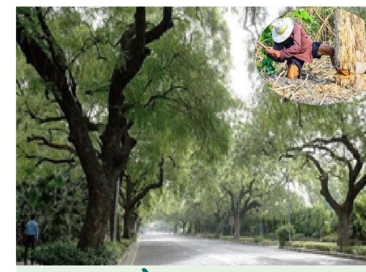
मीडिया ने इस घटना को सनसनीखेज ढंग से दिखाया। शीर्षक आए – ₹हनीमून बना हत्याकांड का अड्डा₹ ₹बेवफा बीवी की खूनी प्लानिंग₹ ₹राजा गया, सोनम हँसी लेकिन इन सुर्खियों के पीछे की वास्तविक पीड़ा, राजा के माता-पिता का दुःख, और समाज में बनती विडंबनाओं की चर्चा लगभग नदारद रही। सोशल मीडिया पर भी मामला जल्दी ही मेमे और चुटकुलों का विषय बन गया – पूरा नॉर्थ ईस्ट सोनम की बेवफाई से बदनाम हो गया। हनीमून पर जाने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी कर लो।

यह हास्य के नाम पर एक मानवीय त्रासदी का उपहास है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह एक अलग-थलग मामला है। लेकिन सच यह है कि ऐसे रिश्ते-जनित अपराध बढ़ रहे हैं। कहीं पति पत्नी को दहेज के लिए मार रहा है। कहीं पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर रही है। कहीं दोनों मिलकर बच्चों को मार डालते हैं। यह सब संकेत हैं – कि हमारा समाज कहीं न कहीं भावनात्मक पतन, सामाजिक अस्थिरता और नैतिक विघटन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अब सवाल समाधान का है।

स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ करियर या डिग्री की बात न हो, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता , रिश्तों की समझ, संवाद की कला और वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों की चर्चा हो। जैसे स्वास्थ्य चेकअप होता है, वैसे ही शादी से पहले मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग अनिवार्य हो। सोशल मीडिया को ऐसी घटनाओं को सनसनी नहीं, संवेदना के साथ पेश करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। परिवारों को संवादशील बनना होगा, ताकि युवा खुलकर अपनी उलझनों को साझा कर सकें। जब एक युवती अपने पति की हत्या करती है, तो हम उसे ₹डायन₹, ₹खूनी₹, ₹बेवफा₹ कह देते हैं – और सही भी है, अगर वह दोषी है। लेकिन क्या हमने कभी उन हजारों बेटियों की सुध ली जो दहेज, बलात्कार, या मारपीट में मर जाती हैं? क्या हम अपराध को सिर्फ लिंग के आधार पर देखेंगे या सिद्धांतों और संवेदनाओं के आधार पर?

राजा की हत्या कोई फिल्मी सस्पेंस नहीं, यह हकीकत है। एक मां का बेटा गया, एक बहन का भाई और एक परिवार की खुशियाँ छिन गईं। वहीं दूसरी ओर – एक राज्य बदनाम हो गया, और पूरे पर्यटन क्षेत्र पर प्रश्नचिन्ह लग गया। हम इस घटना को केवल एक अपराध के रूप में न देखें, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी के रूप में लें। यह हमें बताती है कि अब वकह्वत आ गया है – जब हमें केवल रिश्ते जोड़ने की नहीं, उन्हें निभाने की शिक्षा भी देनी होगी।

डॉ. सत्यवान सौरभ



एक पेड़ काटा अगर तो सौ पेड़ है लगाना

मानवता खतरे में पड़ी है यह सबको है समझाना
प्रकृति से खिलवाड़ नही करना पर्यावरण है बचाना
उन्नति के नाम पर जो हमने काट डाले जंगल
एक पेड़ काटा अगर तो सौ पेड़ है लगाना
पेड़ भी काट दिए काट दी छोटी झाड़ियां
मैदान बना डाली वह सुंदर दिखती पहाड़ियां
छाया के लिए ढूंढता फिर रहा कोई घना पेड़
चुकानी तो पड़ेगी तुझे यह सब देनदारियां
लगा दी आग जंगलों में पक्षी घोंसला कहां बनाएं
पानी के लिए मर रहे अपनी तड़फ किसको दिखाएं
अंडों समेत जल गई उन पर बैठी माता
बच्चों संग मां कैसे जल गई यह उन्हें कैसे समझाएं
प्रकृति से छेड़छाड़ का ही यह है परिणाम
हर वर्ष बादल फटते हैं तूफान और बाढ़ हैं आते
गुनाह करने वाला तो कोई और ही होता है
मरते हैं बहुत लोग बिना कसूर सजा हैं पाते
गंदगी हम फैलाते हैं प्लास्टिक हम हैं जलाते
स्वार्थ सिद्धि के लिए जंगलों में आग हैं लगाते
छोटे पौधे पशु पक्षी और जानवर
इस आग की भेंट हैं चढ़ जाते
कारखानों का कचरा सारा दरिया में हैं बहाते
सब्जियों पर केमिकल का छिड़काव कर हैं बेच आते
बीमार कोई हो जाये सेहत की चिंता नहीं दूसरों की
मरता है कोई तो मर जाये हम तो पैसे हैं कमाते
प्रकृति से खिलवाड़ करोगे नहीं रहेंगे जब यह पेड़
धरा गर्म हो जाएगी फिर हो जाएगा उलटफेर
पर्यावरण को नहीं बचाओगे तो नहीं मिलेगी प्राणवायु
स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा घटती जाएगी आयु
पर्यावरण दिवस नहीं मनाना साल में केवल एक बार
सुरक्षित जीवन जीना है तो मनाइये इसे बारम्बार
अगली पीढ़ी याद करेगी हम सबको
बृक्ष लगा कर करोगे यदि इस धरती का श्रृंगार



रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र



दो कविताएं

1
साहित्य की पुकार

साहित्य न बिकता है, न झुकता है,
वह तो भीतर की लौ में सुलगता है।
ना नाम के पीछे, ना दाम के लिए,
बस सत्य के संग वह चल पड़ता है।
जो शब्द बेचें, सम्मान खरीदें,
वो क्या जानें भावों की पीड़ा।
वढककी रसीद से जो गौरव पाएं,
उनकी लेखनी रहेगी रीता।
झूठे मंच, नकली तमगे,
भाषा को बना रहे हैं मजाक।
हिंदी का ये अपमान देखकर,
क्या अब भी रहेंगे हम चुपचाप?
अब उठो, बहिष्कार करो,
इस छद्म प्रतिष्ठा को नकारो।
साहित्य को साधना रहने दो,
इसे न बिकने दो, न हारो।

2
बेचारा पौधा

बेचारा...
पौधा एक,
फोटो में पच्चीस लोग।
किसी ने पकड़ा गमला,
तो किसी ने थामी टहनी,
किसी ने मुस्कान ओढ़ी,
तो किसी ने झलकाई सहृदयता बहु-अभिनयी।
कंधे से कंधा भिड़ाकर खड़े,
कपड़ों पर प्रेस, चेहरे पर शान,
फोटो खिंच गई –
पर पौधे की प्यास रह गई अनजान।
मुख्यमंत्री जी बोले - हरियाली अभियान!,
नेता जी बोले झ ह्लधरती मां को प्रणाम!ह्व
और वहीं कोने में,
सूरज की धूप में तिलमिलाता,
सूखता गया वो मासूम हरियाण।
अगले दिन अखबार में
बड़ी सी तस्वीर छपी झ
₹हमने एक पौधा लगाया!₹
मगर सच यह था कि
पौधा ही फोटो में कहीं खो गया।
सच पूछो तो
पौधे की जरूरत मिट्टी, पानी और साया थी,
ना कि शाब्दिक घोषणाओं की छाया थी।
हर पौधा पोस्टर नहीं होता।
उसे दिखावे नहीं, देखभाल चाहिए।

- डॉ सत्यवान सौरभ

महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ भंडारे का आयोजन



भंडारा सनातन संस्कृति की प्राचीन परंपरा : महंत राजूदास

गोरखपुर (जीकेबी)। गत दिनों मंगलवार को काली मंदिर गोलघर के सामने हिन्दू सुरक्षा सेवा संघ के तत्वावधान में भंडारे का आयोजन किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भंड़ारे का शुभारंभ करते हुए कहा कि भंड़ारा सनातन संस्कृति की प्राचीन परम्परा है। भंड़ारे के माध्यम से सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। भंड़ारे में प्रसाद ग्रहण करने वाला कोई भी हिन्दू जातियों में नहीं बंटता है। वह गर्व से कहता है कि हम सनातनी हैं। महानगर अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा पल्लू ने मंहत राजू दास को गदा भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर महापौर ड़ा. मंगलेश श्रीवास्तव, उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड.के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, भाजपा महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्त, अच्युतानंद शाही, अजय श्रीवास्तव, मनोज अग्रहरि, अमित गुप्त, पूजा गुप्त, रागिनी जायसवाल, श्वेता श्रीवास्तव, सुधीर यादव, राधेश्याम सिंह, मुन्नालाल शर्मा, विनोद गुप्त, अनूप सोनी, संदीप गुप्त सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। इसी क्रम में अंतिम बड़े.मंगलवार को अधिवक्ताओं ने मंड़लायुक्त कार्यालय के सामने प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण में भंड़ारे का आयोजन किया। शहर के कई गणमान्य लोगों, भक्तगणों व राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी प्रकार से रेती रोड, कोतवाली रोड, नार्मल टैक्सी स्टैंड रोड सहित अनेक स्थलों पर बड़े मंगल के उपलक्ष्य में बजरंग बली के गुणगान एवं उनकी आरती के बीच में भण्डारे का आयोजन किया गया।



भारतीय संस्कृति का वैश्विक संदेश

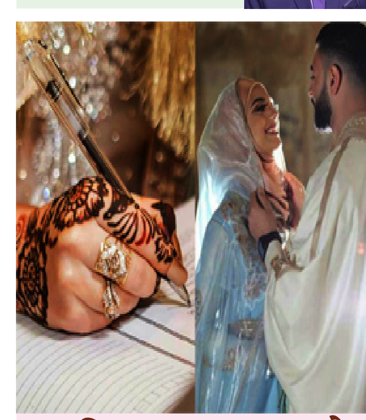
अफगानिस्तान, से लेकर यमन, सीरिया, सूडान और फिलिस्तीन तक कई क्षेत्र आज भीषण हिंसा से जूझ रहे हैं। वहां पर केवल राजनीतिक समाधान नही, मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत अकेले शांति नहीं ला सकता लेकिन भारत की सोच दुनिया को रास्ता दिखा सकती है।

भारत सहिष्णुता और शांति की भूमि है। इस वैश्विक उद्देश्य का सबसे...सशक्त प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम्- अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है' की भावना न केवल धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है बल्कि भारतीय कूटनीतिक, समाज और नागरिक व्यवहार का भी मूलभूत हिस्सा है। ऐसे समय में जब वैश्विक परिदृश्य में स्वार्थ, संघर्ष और सत्ता की होड़ हावी होती जा रही है। भारत की भूमिका और उसकी सोच अंतरराष्ट्रीय शांतिपूर्ण दिवस को एक गहरी प्रासंगिकता प्रदान करती है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां राष्ट्रों के निर्णय मानवीय मूल्यों से अधिक उनके भू-राजनीतिक हितों से संचालित हो रहे हैं। प्रत्येक देश अपने स्वार्थ के अनुसार संबंध बनाता या तोड़ता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग अब केवल तब

दिखाता दिखता है जब उसको सीधा लाभ उस देश को हो। भारत जब आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या से जूझता है तो कई विकसित देश इसे भारत की आंतरिक समस्या कहकर कर्तव्य से पल्ला झाड़ लेते हैं जैसे कि आपरेशन सिंदूर में देखने को मिला किंतु जब भारत ने आत्मरक्षा में बड़े कदम उठाए तो विश्व शांति की दुहाई देने स्वयं तथाकथित शांति सम्राट विश्व पटल पर उभरने लगे! उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि आतंकवाद की जड़ें सीमाओं से परे हैं और इसका असर सारी दुनिया पर पड़ता है। आतंकवादी

गतिविधियां न केवल भारत की शांति को भंग करती हैं बल्कि सभ्यता को संकटों डालती हैं। इसके विपरीत जब तुर्किश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या अफ्रीका के किसी देश में आपदा आती है वो भारत सबसे पहले मदर के लिए हाथ बढ़ाता है। चाहे वह आपरेशन दोस्त हो, कोविड-19 के समय वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम हो या फिर श्रीलंका का आर्थिक कार्यक्रम हो या फिर श्री लंका को आर्थिक आपदा में ईंधन और दवाओं की आपूर्ति। यह भारत की नीति नहीं उसकी परंपरा है, बिना स्वार्थ के शांतिपूर्ण तरीके से मानवता की सेवा।

भारतीय संस्कृति का आधार ही शांति और सह अस्तित्व है। यहां सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना केवल धार्मिक पाठ नहीं है वरन जीवन को जीने का मार्ग है। भारत में विविधताओं के बीच एकता को सबसे बड़ा मूल्य माना गया है। यहां भाषाओं की बहुलता है, धर्मों की विविधता है। परन्तु फिर भी एक सांस्कृतिक धागा सब को जोड़े रखता है। भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया, उसका इतिहास दूसरों को जीतने का नहीं, खुद को सबके साथ जोड़ने का रहा है। अहिंसा केवल महात्मा गांधी का सिद्धांत नहीं रहा है। वह बुद्ध, महावीर, तुलसी, कबीर और नानक की वाणी में भी उतनी ही प्रखर रही है। भारत के संतों और विचारकों ने हमेशा संवाद, करुणा और समरसता को प्राथमिकता दी। भारत ने समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में मध्यस्थता एवं सुलह की भूमिका निभाई है। चाहे वह इसराइल-फिलिस्तीन का संघर्ष हो या रूस-यूक्रेन युद्ध भारत ने कभी किसी पक्ष का अंध समर्थन नहीं किया, बल्कि बातचीत, कटनीति और सहयोग का मार्ग अपनाया। भारत ने युक्रेन को मानवीय सहायता भेजी वहीं रूस के साथ संवाद भी बनाये रखा। यह नीति भारत की पहचान बनती है। संतुलन और संयम हाल में भारत में हुए-जी-20 सम्मेलन का विषय था-वसुधैव कुटुम्बकम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य । यह विषय न केवल भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि, वैश्विक सहयोग सबसे समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भारत ने इस मंच से यह संदेश दिया कि विकास की दौड़ में पिछड़े देशों को छोड़कर कोई भी शांति और समृद्धि टिकाऊ नहीं हो सकती है। सभी को साथ लेकर चलना, संसाधनों की साझेदारी करना और जलवायु परिवर्तन, महामारी, गरीबी, आतंकवाद जैसी समस्याओं से मिलकर लड़ना ही शांति का स्थायी आधार हो सकता है। भारत ने अफ्रीका को आवाज दी। वैश्विक दक्षिण के देशों को प्रतिनिधि दिया और संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यह भारत का वैश्विक दृष्टिकोण है-समावेश, संवाद, और सहयोग यह प्रश्न हम सभी को विचार के लिए प्रेरित करता है। जब भारत सेवा करता है तो वह मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है लेकिन क्या बाकी दुनिया भी यही भावना रखती है। आवश्यकता इस बात की है कि- वैश्विक ताकत अपने हितों से ऊपर उठे और सहयोग एवं समरसता को प्राथमिकता प्रदान करें।



बहुविवाह का दुरुपयोग

इस्लामिक कानून (बहुविवाह संबंधित) का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है वह अत्यंत चिंता का विषय है। इस्लाम के शुरूआती दौर में बहुविवाह समय की मांग थी। इतिहास में एक ऐसा दौर आया जब अरब देशों में कबीलाई संघर्ष के चलते बड़ी संख्या में महिलाएं विधवा होती थीं और बच्चे अनाथ हो जाते थे इन सारी स्थितियों में अनाथ बच्चों और उनकी माताओं को सामाजिक शोषण से बचने के लिए इस्लाम ने सशर्त बहुविवाह की अनुमति दी थी। लेकिन पुरुष अब अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं जिसे किसी भी रूप में उचित नहीं माना जा सकता है क्योंकि अब न वह समय है और न ही वैसी परिस्थितियां हैं। यही कारण है कि- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की भांग भी अपने अस्तित्व में आ रही है। इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस विषय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है कि शरियत कानून के तहत चार शादी पुरुष कर सकता है, बशर्ते सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करे। शरीयत में प्रतिबंधित शादी यानी जिनसे शादी नहीं की जा सकती है करने पर इसे बातिल घोषित करने का प्राविधान नहीं है। ऐसे आवेदन शरीयत कानून के तहत परिवार अदालतों को सुनवाई कर तय करने का क्षेत्राधिकार है जो बिना अधिकार मौलवियों द्वारा किया जा रहा है। शरियत में चार शादियों की अनुमति है। ऐसे में दूसरी शादी धारा 494 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है। इसी आधार पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की अदालत ने द्वि-विवाह के आरोपों की याचिका विचारणीय मानी है। हालांकि कोर्ट ने याची के खिलाफ शुरू की गई याचिका पर अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह सही है कि इस्लामिक शरियत में बहु-विवाह की अनुमति है लेकिन जिस तरह इसकी व्याख्या कर दुरुपयोग किया जा रहा है वह सामाजिक हित में नहीं है, इससे आबादी का संतुलन बिगड़ता है, इस्लामी समाज में प्रचलित इस बहु-विवाह प्रथा को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादक: पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com